

/186172/2024

उत्तराखण्ड शासन
एच्च शिक्षा अनुभाग-3
संख्या: 109/XXIV-C-3/2024-13(11)2018(Comp no 32176)
देहरादून दिनांक 31 जनवरी, 2024

अधिसूचना

राज्यपाल, उत्तराखण्ड निजी विश्वविद्यालय अधिनियम, 2023(उत्तराखण्ड अधिनियम संख्या 02, वर्ष 2024) की धारा 1 की उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए 31 जनवरी, 2024 को ऐसी तारीख के रूप में नियत करते हैं, जिस तारीख को उक्त अधिनियम प्रवृत्त होगा।


Signed by Byomkash Dubey
Date: 31-01-2024 13:22:51

(ब्योमकेश दूबे)
उप सचिव

संख्या : 109 (1)/XXIV-C-3/2024-13(11)2018(Comp no 32176) तददिनांक।
प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
2. समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
3. सचिव, मा0 मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड शासन।
4. सचिव, श्रीराज्यपाल, उत्तराखण्ड, देहरादून।
5. आयुक्त गढ़वाल मण्डल, पौड़ी/कुमाऊँ मण्डल, नैनीताल।
6. समस्त कुलपति, राज्य विश्वविद्यालय, उत्तराखण्ड।
7. समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
8. संयुक्त सचिव, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, बहादुरशाह जफर मार्ग, नई दिल्ली।
9. निदेशक, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली।
10. समस्त कुलपति, निजी विश्वविद्यालय, उत्तराखण्ड।
11. उपनिदेशक, राजकीय गुदणालय एवं लिथोप्रेस, रुड़की, जनपद-हरिद्वार को अधिसूचना को राजपत्र के आगामी अंक में प्रकाशनार्थ।
12. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,


(जे०पी०बेरी)
अनु सचिव

/186372/2024

In pursuance of the provision of Clause (3) of article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following english translation of notification no ..109....., dated..31 Jan 2024

Government of Uttarakhand
Higher Education Section-3
No. /XXIV-C-3/2024-13(11)2018(Comp no 32176)
Dehradun: Date :31st January, 2024

Notification

In exercise of the powers conferred by sub-section (3) of Section 1 of The Uttarakhand Private Universities Act, 2023(Act No. 02 of 2024), the Governor, hereby appoints 31st day of January, 2024 as the date on which the said Act shall come into force.

Signed by Byomkesh Dubey
Date: 31-01-2024 17:05:50
(Byomkesh Dubey)
Deputy Secretary

No. 109(1)/XXIV-C-3/2021-13(11)2018(Comp no 32176), as above date.

Copy to following for information and necessary action:-

1. Chief Secretary, Govt of Uttarakhand.
2. All Additional Chief Secretary /Principal Secretary/ Secretary, Govt of Uttarakhand.
3. Secretary, Hon'ble Chief Minister, Govt of Uttarakhand.
4. Secretary, Governor of Uttarakhand.
5. commissioner, garhwal mandal pauri/ kumaon mandal, nainital.
6. All Vice-Chancellor, State University of Uttarakhand.
7. All District Magistrate, Uttarakhand.
8. Joint Secretary, University Grants Commission, Bahadur Shah Zafar Marg, New Delhi.
9. Director, Ministry of Human Resource Development, Govt of India, New Delhi.
10. All Vice-Chancellor, Private University of Uttarakhand.
11. Joint Director, Government printing and Litho press, Roorkee District Haridwar for Publication of above Notification in Government Gazette of upcoming issue.
12. Guard File.

Signed by J P Beri
Date: 31-01-2024 17:07:18

(J P Beri)
Under Secretary



सरकारी गजट, उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग-1, खण्ड (क)
(उत्तराखण्ड अधिनियम)

देहरादून, बुधवार, 03 जनवरी, 2024 ई०

पौष 13, 1945 शक सम्वत्

उत्तराखण्ड शासन

विधायी एवं संसदीय कार्य विभाग

संख्या 02/XXXVI (3)/2024/58(1)/2023

देहरादून, 03 जनवरी, 2024

अधिसूचना

विषय

“भारत का संविधान” के अनुच्छेद 200 के अधीन मा० राज्यपाल ने उत्तराखण्ड विधान सभा द्वारा पारित ‘उत्तराखण्ड निजी विश्वविद्यालय विधेयक, 2023’ पर दिनांक 01 जनवरी, 2024 को अनुमति प्रदान की और वह उत्तराखण्ड राज्य का अधिनियम संख्या: 02, वर्ष-2024 के रूप में सर्व-साधारण के सूचनार्थ इस अधिसूचना द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

उत्तराखण्ड निजी विश्वविद्यालय अधिनियम, 2023

(उत्तराखण्ड अधिनियम संख्या 02, वर्ष 2024)

अनुक्रमिका

धाराएं	विवरण	पृष्ठ संख्या
	अध्याय-1	
	प्रारम्भिक	
1	संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारम्भ	6
2	परिभाषाएं	6-10
	अध्याय-2	
	विश्वविद्यालय की स्थापना	
3	विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए शर्तें	10
4	विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए प्रस्ताव प्रस्तुत करना	11
5	प्रस्तावों का मूल्यांकन एवं संस्तुति	11
6	'आशय पत्र' जारी किया जाना एवं प्रायोजक निकाय द्वारा अनुपालन आश्वासन जमा किया जाना	11
7	विश्वविद्यालय की स्थापना	11-12
	अध्याय-3	
	विश्वविद्यालय का निगमन एवं उसके उद्देश्य	
8	विश्वविद्यालय का निगमन	12
9	विश्वविद्यालय के उद्देश्य	13
10	विश्वविद्यालय की शक्तियाँ	13-16
11	प्रवेश एवं शैक्षणिक मानक	16
12	विश्वविद्यालय का सभी वर्गों और नतावलम्बियों के लिए खुला होना	16
13	उत्तराखण्ड राज्य के स्थायी निवासियों हेतु उपबन्ध	17
14	किसी संस्था को सम्बद्ध करने की शक्ति का न होना	17
	अध्याय-4	
	विश्वविद्यालय के अधिकारी	
15	विश्वविद्यालय के अधिकारी	17-18
16	कुलाध्यक्ष	18
17	अध्यक्ष	18-19
18	कुलपति	19-20

19.	कुलपति की शक्तियाँ एवं कर्तव्य	20-21
20.	प्रति-कुलपति	21-22
21.	संकायाध्यक्ष/प्राचार्य/निदेशक	22
22.	कुलसचिव	22
23.	वित्त अधिकारी	22
24.	परीक्षा नियंत्रक	22-23
25.	अन्य अधिकारी	23
	अध्याय-5	
	विश्वविद्यालय के प्राधिकरण	
26.	विश्वविद्यालय के प्राधिकरण	23
27.	व्यवस्थापक मण्डल	23-25
28.	प्रबन्धन मण्डल	25
29.	विद्या परिषद्	25
30.	परीक्षा मण्डल	25
31.	पाठ्यक्रम मण्डल	25
32.	योजना मण्डल	25
33.	वित्त समिति	25
34.	विश्वविद्यालय के अन्य प्राधिकरण	25
35.	किसी प्राधिकरण या निकाय के सदस्यों हेतु अनर्हता	25
	अध्याय-6	
	परिनिर्णय, अध्यादेश एवं विनियम	
36.	परिनिर्णय बनाने की शक्ति	27-28
37.	अध्यादेश बनाने की शक्ति	28-29
38.	विनियम बनाने की शक्ति	29
39.	परिनिर्णयों, अध्यादेशों एवं विनियमों का प्रकाशन	29
40.	दीक्षान्त समारोह	30
41.	विश्वविद्यालय का प्रशासन	30
	अध्याय-7	
	विश्वविद्यालय की निधि एवं खाते	
42.	छात्रों विन्यास निधि	30
43.	सामान्य निधि	30-31
44.	विकास निधि	31
45.	निधियों का अनुरक्षण	31
46.	वार्षिक प्रतिवेदन	31

47.	वार्षिक लेखा एवं लेखा परीक्षा	31-32
48.	विश्वविद्यालय स्वयत्तप्राप्ति होगा	32
	अध्याय-8	
	राज्य सरकार एवं नियामक निकायों की भूमिका	
49.	विश्वविद्यालय द्वारा नियामक निकायों के नियम, विनियम, मानक आदि का अनुसरण	32
50.	सूचना और अभिलेखों की मांग करने के लिए राज्य सरकार की शक्ति	32
51.	राज्य सरकार एवं नियामक निकायों की भूमिका	33
52.	शुल्क	33-34
53.	एफ़ड का प्रावधान	34-35
	अध्याय-9	
	विश्वविद्यालय का विघटन/परिसमापन	
54.	विश्वविद्यालय का विघटन/परिसमापन	35-36
55.	विघटन/परिसमापन के दौरान विश्वविद्यालय के व्यय	36
	अध्याय-10	
	प्रकीर्ण और संक्रमणकालीन उपबन्ध	
56.	शिक्षकों का कर्तव्य	36
57.	परीक्षा संबंधी कार्य करने की वाध्यता	36
58.	विवरणी और जानकारी	36
59.	कर्मचारियों की सेवा शर्तें आदि	36-37
60.	अपील का अधिकार	37
61.	शिकायत निवारण समिति	37
62.	मध्यस्थ निधि एवं पेशान	37
63.	प्राधिकरणों और निकायों के गठन संबंधी विवाद	37
64.	आंतरिक रिक्तियों की पूर्ति	37
65.	रिक्तियों के कारण प्राधिकरणों और निकायों की कार्यवाही का अमान्य न होना	38
66.	सदभावपूर्वक की गयी कार्यवाही के प्रति संरक्षण	38
67.	विश्वविद्यालय के अभिलेखों को प्रमाणित करने की विधि	38
68.	सरकार की नियम बनाने की शक्ति	38
69.	कठिनाईयों के निवारण की शक्ति	38
70.	उत्तराखण्ड के न्यायालय में विवादों का निस्तारण	38
71.	अध्यापक प्रभाव	38

72	निस्सन और व्यापृति	39
73	सकम्पकालीन सपहन्ध	39
74	अल्पसंख्यक निजी विश्वविद्यालय	39

उत्तराखण्ड निजी विश्वविद्यालय अधिनियम, 2023

(उत्तराखण्ड अधिनियम संख्या 02, वर्ष 2024)

गुणवत्तापूर्ण बहु-विषयक एवं उद्योग-प्राधानिक उच्च शिक्षा प्रदान करने हेतु उत्तराखण्ड राज्य में नए निजी विश्वविद्यालयों को नियमित व स्थापित करने तथा विद्यमान निजी विश्वविद्यालयों को अधिनियमों का निरसन कर इस अधिनियम के अधीन नियमित व स्थापित करने तथा उनके कर्तव्यों को सनातन रूप से विनियमित करने और उनसे सम्बन्धित या आनुबन्धिक विषयों की व्यवस्था करने के लिये

अधिनियम

भारत गणराज्य के चौदहवाँ वर्ष में उत्तराखण्ड राज्य विधानसभा द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो:-

अध्याय 1

प्रारम्भिक

संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ	1.	(1)	इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम उत्तराखण्ड निजी विश्वविद्यालय अधिनियम, 2023 ई।
		(2)	इसका विस्तार सम्पूर्ण उत्तराखण्ड राज्य पर होगा।
		(3)	यह उस दिनांक को प्रवृत्त होगा जो राज्य सरकार गजट में अधिसूचना द्वारा, निवृत्त करे।
परिभाषाएँ	2.	यह तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो इस अधिनियम में, -	
		(क)	"अधिनियम" से उत्तराखण्ड निजी विश्वविद्यालय अधिनियम, 2023 अभिप्रेत है;
		(ख)	"विद्या परिषद्" से विश्वविद्यालय की विद्या परिषद् अभिप्रेत है;
		(ग)	"प्राधिकरण" से विश्वविद्यालय के प्राधिकरण अभिप्रेत है;
		(घ)	"व्यवस्थापक मण्डल" से विश्वविद्यालय का व्यवस्थापक मण्डल अभिप्रेत है;
		(ङ)	"प्रबन्धन मण्डल" से विश्वविद्यालय का प्रबन्धन मण्डल अभिप्रेत है;
		(च)	"निकाय" से विश्वविद्यालय के किसी अधिकारी या प्राधिकारी द्वारा बनाया गया निकाय अभिप्रेत है;

	(ग)	"प्रति व्यक्ति शुल्क (कंविटेशन शुल्क)" से ऐसा शुल्क अभिप्रेत है जिसे निर्धारित व सार्वजनिक रूप में प्रदर्शित शुल्क के अतिरिक्त नकद या अन्य किसी वस्तु में लिया जाये;
	(ज)	"महाविद्यालय/संस्थान/विद्यालय" से विश्वविद्यालय द्वारा स्थापित व प्रबन्धित महाविद्यालय या संस्थान या विद्यालय अभिप्रेत है;
	(झ)	"परीक्षा नियंत्रक" से विश्वविद्यालय का परीक्षा नियंत्रक अभिप्रेत है;
	(ञ)	"संकायाध्यक्ष" से विश्वविद्यालय के किसी संकाय का संकायाध्यक्ष अभिप्रेत है;
	(ट)	"विभाग" से अध्यादेशों या विनियमों द्वारा किसी विषय या विषय के समूह हेतु नामनिर्दिष्ट विभाग अभिप्रेत है;
	(ठ)	"निदेशक" से विश्वविद्यालय के किसी संस्थान, विश्वविद्यालय के किसी केंद्र सहित, का प्रधान अभिप्रेत है;
	(ड)	"कर्मचारी" से विश्वविद्यालय द्वारा नियुक्त कोई कर्मचारी जिसमें अध्यापक एवं अन्य कर्मचारी भी सम्मिलित हैं, अभिप्रेत है;
	(ढ)	"मूल्यांकन समिति" से निजी विश्वविद्यालयों की स्थापना हेतु प्राप्त प्रस्तावों के मूल्यांकन हेतु गठित मूल्यांकन समिति अभिप्रेत है;
	(ण)	"संकाय" से विश्वविद्यालय का संकाय जिसमें कुछ विभाग सम्मिलित हो अभिप्रेत है;
	(त)	"वित्त समिति" से विश्वविद्यालय की वित्त समिति अभिप्रेत है;
	(थ)	"वित्त अधिकारी/वित्त नियंत्रक" से विश्वविद्यालय का वित्त अधिकारी/वित्त नियंत्रक अभिप्रेत है;
	(द)	"उच्च स्तरीय समिति" से इस अधिनियम के अन्तर्गत उत्तराखण्ड राज्य में निजी विश्वविद्यालयों की स्थापना के प्रस्तावों की संस्तुति करने हेतु गठित उच्च स्तरीय समिति अभिप्रेत है;
	(ब)	"उच्च शिक्षा" से 10+2 स्तर के ज्ञान से आगे के पाठ्यक्रमों या पाठ्यक्रम का अध्ययन अभिप्रेत है;

	(न)	"पर्वतीय क्षेत्र" से ऐसे क्षेत्र, ब्लॉक या जिले, जिसे उत्तराखण्ड राज्य द्वारा अपनी नवीनतम अधिसूचना से पर्वतीय क्षेत्र परिभाषित किए गए हों अभिप्रेत है।
	(प)	"छात्रावास" से इस अधिनियम या परिनिधनी या अध्यादेशों के उपबन्धों के अनुरूप विश्वविद्यालय अथवा विश्वविद्यालय के संघटक या अनुरक्षित महाविद्यालयों या संस्थानों के छात्रों के लिए आवास की एक इकाई अभिप्रेत है।
	(क)	"मुख्य परिसर" से उत्तराखण्ड राज्य में स्थित निजी विश्वविद्यालय का मुख्य परिसर जिसमें एक ही स्थान पर कम से कम पांच शैक्षणिक विभागों सहित विश्वविद्यालय का मुख्यालय सम्मिलित हो, अभिप्रेत है।
	(ख)	"गैर परिसर केंद्र/परिसर" से निजी विश्वविद्यालय द्वारा उत्तराखण्ड की सीमा के भीतर विश्वविद्यालय अनुदान आयोग एवं राज्य सरकार की पूर्वानुमति से मुख्य परिसर से बाहर इसके संघटक इकाई के रूप में स्थापित, संचालित एवं अनुरक्षित केंद्र/परिसर अभिप्रेत है।
	(ग)	"अपवासी परिसर" से भारत सरकार एवं अतिथि देश की पूर्वानुमति से निजी विश्वविद्यालय द्वारा देश के बाहर इसकी संघटक इकाई के रूप में स्थापित, संचालित एवं अनुरक्षित परिसर अभिप्रेत है।
	(घ)	"विश्वविद्यालय के अधिकारी" से विश्वविद्यालय के अधिकारी अभिप्रेत है।
	(च)	"अध्यादेश" से इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन बनाये गये विश्वविद्यालय के अध्यादेश अभिप्रेत है।
	(चक)	"स्थायी निवासी" से राज्य का ऐसा निवासी अभिप्रेत है, जिसके पास राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर बनाए गए नियमों के अनुसार भूल निवास/स्थायी निवास प्रमाण-पत्र है।
	(चख)	"विहित" से इस अधिनियम के अधीन बनाये गये परिनिधनी, अध्यादेशों अथवा विनियमों द्वारा विहित अभिप्रेत है।
	(चग)	"अध्यक्ष" से विश्वविद्यालय का अध्यक्ष अभिप्रेत है।
	(चघ)	"प्राचार्य" से विश्वविद्यालय के किसी परिसर कॉलेज का प्राचार्य अभिप्रेत है।

(यह)	प्रति कुलनाते से विरजितालय का प्रति-कुलनाते अभिप्रेत है
(यह)	कुलनाते से विरजितालय का कुलनाते अभिप्रेत है
(यह)	विनियम से इस अधिनियम के अधीन बनाये गये विरजितालय के विनियम अभिप्रेत है;
(यह)	नियामक निकाय से समय-समय पर केन्द्र/राज्य सरकारों द्वारा स्थापित नियामक निकाय जैसे विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् भारतीय वैद्यक परिषद् राष्ट्रीय आधुनिकीकरण परिषद् भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् भारतीय भेषजी परिषद् भारतीय उपभोग्य परिषद् भारतीय दन्त परिषद्, केन्द्रीय होम्योपैथी परिषद् भारतीय कृषि अनुसन्धान परिषद्, दारुनायक परिषद्, दूरस्थ शिक्षा परिषद्, भारतीय पुनर्वास परिषद् राष्ट्रीय प्रामीण संस्थान परिषद् आदि अभिप्रेत है,
(यह)	अनुसूची से इस अधिनियम में संलग्न अनुसूची अभिप्रेत है,
(यह)	प्रादेशिक निकाय से इस अधिनियम के अधीन विश्वविद्यालय स्थापित करने वाली:-
	(एक) उत्तराखण्ड रजिस्ट्रेशन अधिनियम, 1880 (अधिनियम संख्या 21 सन् 1880) या राज्य में तत्काल प्रवृत्त विधि द्वारा स्थापित किसी अन्य अधिनियम के अधीन लागू के बिना कार्य करने वाली उत्तराखण्ड राज्य में रजिस्ट्रीकृत कोई संस्था या
	(दो) भारतीय न्याय अधिनियम 1882 (अधिनियम सं 2 वर्ष 1882) के अधीन रजिस्ट्रीकृत कोई लोक न्याय का
	(तीन) कम्पनी अधिनियम 1956 (अधिनियम सं 01 वर्ष 1956) के अधीन रजिस्ट्रीकृत कोई कम्पनी, या
	(चार) कम्पनी अधिनियम 2013 के अधीन रजिस्ट्रीकृत कोई कम्पनी अभिप्रेत है
(यह)	राज्य में उत्तराखण्ड राज्य अभिप्रेत है

	(घ) परिनिधम से इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन इनके पाठ विश्वविद्यालय के अधिनियम अभिप्रेत है।
	(घक) अध्ययन केन्द्र से विश्वविद्यालय अनुदान आयोग एवं राज्य सरकार की दृष्टिगत से दूरस्थ शिक्षा कार्यक्रम में छात्रों को सहायता देने पर अन्य कोई आवश्यक सहायता प्रदान करने हेतु विश्वविद्यालय द्वारा स्थापित एवं अनुसूचित या मान्यता प्राप्त केन्द्र अभिप्रेत है।
	(घट) छात्र से निजी विश्वविद्यालयों द्वारा संचालित कोई उपाधि (डिग्री) डिप्लोमा या अन्य पाठ्यक्रम जिसमें अनुसंधान भी सम्मिलित है हेतु विश्वविद्यालय में स्थापित कोई व्यक्ति अभिप्रेत है।
	(घण) अध्ययन के निवारक विकास द्वारा निर्धारित अर्हता के अनुसार नियुक्त कोई आचार्य राह आचार्य सहायक आचार्य/व्याख्याता या ऐसा अन्य व्यक्ति जिसको द्वारा विश्वविद्यालय ने अध्ययनरत किसी छात्र को शिक्षा प्रदान करना अथवा अनुसंधान के लिए मार्गदर्शन करना या अन्य किसी भी प्रकार से मार्गदर्शन करना अपेक्षित हो, अभिप्रेत है।
	(घत) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम 1956 की धारा 4 के अन्तर्गत स्थापित विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अभिप्रेत है।
	(घथ) विश्वविद्यालय से इस अधिनियम के प्रख्यानों के अधीन राज्य में निर्गमित व स्थापित निजी विश्वविद्यालय अभिप्रेत है।
	(घद) कुलपति से विश्वविद्यालय का कुलपति अभिप्रेत है और
	(घध) कुलपति से विश्वविद्यालय का कुलपति अभिप्रेत है।

अध्याय -2

विश्वविद्यालय की स्थापना

विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए शर्तें	3 प्रायोगिक विकास, इस अधिनियम के अधीन निजी विश्वविद्यालय स्थापित एवं संचालित करने हेतु राज्य सरकार और नियोजक विकास द्वारा इन सम्बन्ध में समग्र-समग्र पर अभिलेखन द्वारा जारी दिश-निर्देशों और निर्देशों की शर्तों की शर्तों का प्रत्यक्ष प्रयोग।
--	---

विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए प्रस्ताव प्रस्तुत करना	4 प्रायोजक विभाग या राज्य विधानमंडल के द्वारा पारित अधिनियम के अधीन कि विश्वविद्यालय स्थापित करने के इच्छुक हो राज्य सरकार को एक आवेदन देगा जिसमें अन्य सूचनाओं के साथ प्रस्तावित विश्वविद्यालय की उद्देश्य की रूप-रेखा एवं दृष्टि (विजन), प्रस्ताव तथा प्रायोजक का उद्देश्य एवं ऐसा क्यों एवं ऐसा क्यों सम्बन्धित होगा जैसा सम्भव-सम्भव या राज्य सरकार द्वारा निर्धारित किया जाये।
प्रस्तावों का मूल्यांकन एवं संरक्षित	5 विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए प्रस्ताव तथा परीक्षण आख्या को जर्नल पर राज्य सरकार का उच्च शिक्षा विभाग दिहित प्रणाली में प्रस्तावों का मूल्यांकन करने हेतु एक मूल्यांकन समिति एवं प्रस्तावों की संरक्षित हेतु एक उच्च स्तरीय समिति का गठन करेगा।
प्रस्ताव एवं जारी किया जाना एवं प्रायोजक विभाग द्वारा अनुपालन आख्या प्रेषित किया जाना	6 प्रायोजक के प्रस्ताव को उच्च स्तरीय समिति की अध्यक्षता होगी जो परामर्श देते राज्य सरकार का यह समाधान हो जाता है कि विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए प्रस्तावों को प्रेषित है तो यह प्रायोजक विभाग का एक आदेश पर जारी करेगी।
विश्वविद्यालय की स्थापना	7 (1) यदि राज्य सरकार का समाधान हो जाता है कि प्रायोजक विभाग द्वारा विश्वविद्यालय स्थापित करने हेतु धारा-3 की सभी शर्तों व धारा-8 की धारा-8 के अन्तर्गत एक शर्तों का अनुपालन करने लिया गया है तो यह धारा-8 का उपधारा 2) के प्रावधानों के अन्तर्गत विश्वविद्यालय को निर्माण करने के परमाणु राज्य सरकार में अधिनियम द्वारा ऐसा नाम एवं स्थान में विश्वविद्यालय की स्थापित व संचालन करने की अनुमति देगी। (2) जहाँ सरकार विश्वविद्यालय को कार्य संचालन प्रारम्भ करने के लिए जारी किया गये प्रायोजक-धन की धारिता के उपरान्त ही विश्वविद्यालय अपना कार्य प्रारम्भ करेगा। (3) विश्वविद्यालय स्थापित करने के उपरान्त वह स्थापित विश्वविद्यालय का नाम इस अधिनियम की अनुसूची-2 में उल्लेखित किया जाएगा। (4) विश्वविद्यालय के लिए बजट/संगठन निर्देश/संगठन धर्म भवन और अन्य आवश्यक संरचना का उपकरण द्वारा प्रदान किया जाएगा इसका अधिग्रहण अथवा निर्माण किया गया है, कि विवाद अन्य किसी उद्देश्य के लिए नहीं किया जा सकता।

	(5) विश्वविद्यालय को समस्त संशोधन विद्यार्थियों के निम्नलिखित शर्तों पर नियंत्रित करने पर विश्वविद्यालय के किसी भी उपाध्यक्ष अधिकारी या प्राध्यापक के किसी सदस्य का व्यक्तित्व अथवा व्यक्तिगत हक नहीं होगा।
	(6) विश्वविद्यालय अपने कार्यों को किन्हीं अन्य संस्थानों/व्यक्तियों को निजी अनुसंधान संस्थानों के साथ संयोजित व्यवस्था के द्वारा प्रदान नहीं करेगा चाहे पाठ्यक्रमों को दूरस्थ शिक्षा पद्धति के माध्यम से संचालित किया जाना हो।
	(7) विश्वविद्यालय अस्तित्व में आने के बाद सभी के परामर्श तथा मुख्य परामर्श के निहित होने के उपरान्त राज्य सरकार का पूर्णतया ही अन्य परामर्श और परामर्श केन्द्र अस्तित्व में रहना एवं अध्ययन केन्द्र स्थापित कर सकना। परन्तु यह कि विश्वविद्यालय द्वारा मुख्य परामर्श से शेष अन्य परामर्श और परामर्श केन्द्र अस्तित्व में रहना एवं अध्ययन केन्द्र स्थापित करने के लिए समस्त-समाज, व. विश्वविद्यालय अनुदान आयोग नियामक निकायों द्वारा जारी दिशेषिका का अनुपालन किया जाएगा।

अध्याय -3

विश्वविद्यालय का निगमन एवं उसके एजेंडरय

विश्वविद्यालय का निगमन	(1) इस अधिनियम के तहत होने पर अनुसूची-1 में निर्दिष्ट विधायक निम्न विश्वविद्यालयों को इस अधिनियम के प्रावधानों के अन्तर्गत नियंत्रित कर दिया जाएगा।
	(2) अधीन सुप्रीम कोर्ट द्वारा स्थापित निकायों के तहत एवं विश्वविद्यालय के तहत कुलपति को इस प्रकार स्थापित विश्वविद्यालय में इस प्रकार नए प्रवेश केन्द्र हुए हैं विश्वविद्यालय के तहत एक निगमन निकाय का गठन करेगा।
	(3) विश्वविद्यालय को स्थापित करने के लिए एक राज्य सरकार द्वारा स्थापित तथा वह अपने नाम से बांध लायेगा और उस पर बांध लाया जा सकेगा।
	(4) राज्य सरकार समस्त-समाज पर से सब विधायकता के अधिनियमित कर एवं अधिकाधिक राज्य सरकार में अधिसूचना जारी कर किसी भी निकाय को विश्वविद्यालय को नियमित कर सकेगा या इस अधिनियम के अधीन निकाय किसी विश्वविद्यालय के स्थापन एवं कार्य करने के क्षेत्र को घट कर या बढ़ा सकता है।

	(ब)	गुल्क और अन्य प्रभारों का निर्धारण करना भंग करने और उनके भुगतान प्राप्त करना
	(द)	गर्मी भोंदों के कर्मचारियों की आवश्यक नियमावली तैयार करना और उसे लागू करना
	(ध)	गर्मी भोंदों पर अन्य दायित्वों के सम्बन्ध में विवेक प्रदर्शित करना और उनके विवरणों का संचालन करना
	(नि)	विश्वविद्यालय के छात्रों और कर्मचारियों के मध्य अनुदानों के वितरण करना और प्रवर्तित करना और इस सम्बन्ध में ऐसे विवरणों को तैयार करना जैसा कि विश्वविद्यालय द्वारा आवश्यक समझा जाय
	(प)	विश्वविद्यालय के कर्मचारियों के स्वास्थ्य और सामान्य कल्याण के सतर्कता के लिए व्यवस्था करना
	(फ)	प्रायोजक निवास के पूर्व अनुमति एवं परिश्रमों अधीन संचालित करने के उपरान्त को अनुसंधान विश्वविद्यालय की दान सम्पत्ति का निस्तारित करना
	(ब)	विश्वविद्यालय के अलावा के लिए दान प्राप्त करना और किसी दान का अथवा सम्पत्ति का अर्जन, धारण और प्रवर्धन करना
	(भ)	व्यवस्थापक मण्डल तथा प्रायोजक निवास के अनुमोदन पर विश्वविद्यालय के प्रयोजनाधी विश्वविद्यालय की सम्पत्ति या प्राप्त हुए सुख पर धन मुद्रा का एकत्रित करना स्वीकार करना तथा जमा लेना
	(ग)	यह सुनिश्चित करना कि दान सम्पत्ति के पूर्व अनुमोदन के विना विश्वविद्यालय के किसी अधिकारी या प्रायोजक द्वारा केलो अथवा समाने का निस्तारण या उसमें उसका कोई अधिकार या हक होने या इस पर गुंजित किसी दानदारी से उसे पृथक् नहीं किया जायेगा
	(घ)	गर्मी भोंदों या अन्य दायित्वों आधार पर ऐसे अनुदानों आचार्य निदेशिका परामर्शदाताओं अधीन विद्युती कर्मचारी दायित्व निदेशिका और ऐसे अन्य दायित्वों का निस्तारण करना जो विश्वविद्यालय के उद्देश्यों को अंगर करने में योगदान प्रदान कर सकें
	(चक)	समस्त उद्देश्यों वाली सहायता सामाजिक सहायता तथा धार्मिक सहायता का दान या अनुदान देना या सहायता प्रदान करना
	(गिध)	यह अनुदान और प्रसार सेवा का आयोजन करना और दायित्व प्रदान करना

		(दस)	विश्वविद्यालयों और छात्रों के लिए अभियोगों पर पाठ्यक्रम पुनरीक्षण पाठ्यक्रम कार्यशालाओं सम्मेलनों एवं अन्य कार्यक्रमों का आयोजन तथा संचालन करना।
		(गघ)	महिलाओं को शिक्षित करना, कार्योन्मुख करना, उसमें परिवर्तन या उत्तम सहायक करना।
		(घक)	अन्य विश्वविद्यालयों संस्थानों एवं उच्च शिक्षा के अन्य संस्थाओं की परीक्षाओं अथवा अध्ययन की अवधि (पूर्ण या आंशिक) को विश्वविद्यालयों की परीक्षाओं अथवा अध्ययन की अवधि के समतुल्य मान्यता प्रदान करना तथा दी गयी ऐसी मान्यता को किसी भी समय समाप्त करना।
		(घघ)	विश्वविद्यालय अनुदान आयोग विधायक नियुक्त तथा राज्य सरकार के अनुमोदन से दूरस्थ पद्धति में शिक्षा प्रदान करना और
		(घघ)	ऐसी अन्य समस्त कार्य और कृत्य करना जो विश्वविद्यालय के सुदूर संचालन व उसके सभी या किसी उद्देश्यों की प्रगति के लिए आवश्यक आनुवांशिक या सहायक हों।
प्रवेश और शैक्षणिक मानक	11	(1)	विश्वविद्यालय ने संबन्धित सभी शैक्षणिक कार्यक्रमों में प्रवेश अधिनियम तदधीन बनाये गये परिनिषेधों तथा अध्यादेशों से उपबन्धों द्वारा अध्यापित किये गये प्रतिभागी के अनुसार प्रवेश समिति द्वारा किये जायेंगे।
		(2)	विश्वविद्यालय यह सुनिश्चित करेगा कि विश्वविद्यालय द्वारा प्रस्तुत किये गये पाठ्यक्रमों के शैक्षणिक भागक विधायक नियुक्तों के दिशा-निर्देशों के अनुसार हों।
		(3)	अध्ययक-छात्र अनुमति विनियमनक नियमों के दिशा-निर्देशों के अनुसार होंगे।
विश्वविद्यालय का सभी वर्गों और गतावसन्धियों के लिए खुला होना	12		विश्वविद्यालय सभी लिंग और रंग, जाति या वर्ग के व्यक्तियों के लिए खुला होगा और विश्वविद्यालय के लिए यह विधिसम्मत नहीं होगा कि यह किसी व्यक्ति के लिए किसी अधिकारी अध्यापक कर्मचारीवृन्द सदस्य छात्र के रूप में उसने प्रवेश किए जाने के लिए या उसमें पद धारण करने के लिए या वही से स्वागत करने के लिए हकदार करने के उद्देश्य से वार्षिक विश्राम या व्यवसाय की कोई परीक्षा, जो भी हो ले या उस पर अतिरिक्त करे परन्तु यह कि इस धारा की कोई बात विश्वविद्यालय को उत्तराखण्ड राज्य के स्थानीय निवासियों को विश्वविद्यालय द्वारा संचालित विभिन्न पाठ्यक्रमों में प्रवेश हेतु दिशा उपबन्ध करने के लिए विवक्षित किया जाना नहीं समझा जावेगा।

उत्तराखण्ड राज्य के स्थायी निवासियों हेतु उपबन्ध	13	<p>(1) इस अधिनियम में किसी बात के होते हुए भी निजी विश्वविद्यालय द्वारा संचालित समस्त पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए न्यूनतम 25 (पच्चीस) प्रतिशत अथवा शपथ पत्र में घोषित प्रतिशत सीटें उत्तराखण्ड राज्य के स्थायी निवासियों के लिए आरक्षित होंगी।</p> <p>परन्तु यह कि यदि उत्तराखण्ड के स्थायी निवासियों के लिए आरक्षित सीटों में से कुछ सीटें रिक्त रहती हैं तो उस दशा में विश्वविद्यालय द्वारा एक अन्तिम लिखित निर्धारित कर प्रकाशित की जायेगी विश्वविद्यालय द्वारा इस प्रकार निर्धारित अन्तिम लिखित तब तक यदि उत्तराखण्ड के स्थायी निवासी उपलब्ध न हों तो इन सीटों को विश्वविद्यालय अन्य योग्य अभ्यर्थियों द्वारा भरा जा सकेगा।</p> <p>परन्तु यह और कि विश्वविद्यालय द्वारा उत्तराखण्ड के स्थायी निवासियों हेतु आरक्षित सीटों पर राज्य सरकार की तत्कालीन आरक्षण नीति लागू की जायेगी।</p>
		<p>(2) निजी विश्वविद्यालय द्वारा संचालित विभिन्न कार्यक्रमों के शिक्षण शुल्क में उपरोक्त उपधारा (1) के अधीन प्रवेश लेने वाले उत्तराखण्ड राज्य के स्थायी निवासियों को कम से कम 25 (पच्चीस) प्रतिशत अथवा शपथ पत्र में घोषित प्रतिशत की छूट प्रदान की जायेगी।</p>
		<p>(3) समूह 'अ' एवं 'ब' के समस्त पदों/पदिकाओं पर उत्तराखण्ड राज्य के प्रभुता प्राप्त स्थायी निवासियों को नियुक्ति दी जायेगी।</p>
किसी संस्था को सम्बद्ध करने की शक्ति का न होना	14	<p>विश्वविद्यालय के अपने स्वयं के संघटक संस्थान/महाविद्यालय क्षेत्रीय केन्द्र, अध्ययन केन्द्र व प्रशिक्षण व अनुसंधान केन्द्र हो सकते हैं किन्तु विश्वविद्यालय को किसी भी महाविद्यालय/संस्थान आदि को सम्बद्ध करने की शक्ति नहीं होगी।</p>

अध्याय -4 विश्वविद्यालय के अधिकारी

विश्वविद्यालय के अधिकारी	15.	विश्वविद्यालय के निम्नलिखित अधिकारी होंगे अर्थात् -
		(क) कुलपति
		(ख) अध्यापक
		(ग) कुलपति
		(घ) प्रति-कुलपति
		(ङ) रजिस्ट्रार, प्राचार्य/निदेशक
		(च) कुलसचिव
		(छ) वित्त अधिकारी

		(अ) धरीला नियंत्रक तथा
		(अ) ऐसे अन्य अधिकारी जिन्हें विश्वविद्यालय के अधीनस्थ परिभाषित एवं घोषित किया जाय;
कुम्हार	16	(1) उत्तराखण्ड के राज्यपाल विश्वविद्यालय के कुम्हारों को
		(2) कुम्हारों एवं उनके हों को विश्वविद्यालय के शिक्षण कार्यों के अध्यक्षता करेंगे।
		(3) समस्त उच्च शिक्षण करने वाले कुम्हारों पर उत्तराखण्ड कुम्हारों में प्रयुक्त होने वाले अर्थों का
		(4) उत्तराखण्ड के नियमित शिक्षण हों में शामिल
		(क) विश्वविद्यालय के मानकों से संबंधित शिक्षण को दृष्टिगत या सुधारण कर सकेंगे
		(ख) कुम्हारों को तथा कुम्हारों के अधिकार पर उनके पास सम्पत्ति हो जाता है कि कोई आदेश कार्यपत्र या निर्देश या विश्वविद्यालय के किसी भी प्राधिकारी द्वारा दिया गया हो अध्यापन वित्तियोग, वेतन, शिक्षण अधिकांश या अधिकांश के अनुसंधान नहीं है तो वह ऐसे निर्देश जारी कर सकती है, यदि वह विश्वविद्यालय के हिस में उचित समझे और इस प्रकार जारी किए गए निर्देशों का सभी संबंधित पदव्यक्तियों द्वारा अनुपालन किया जावेगा।
अध्यापक	17	(1) अध्यापकों के नियुक्ति तथा विराम प्रक्रिया परीक्षाओं के नियमों में एक शर्तों का अनुसरण करने वाले होंगे और वे ही अधिकारी के लिए प्राचार्यक विकास द्वारा की जायेगी
		परन्तु यह कि प्राचार्यक विकास द्वारा उसे पुन विचार किया जा सकता।
		(2) अध्यापक विश्वविद्यालय का प्रमुख होगा, वह अध्यापक के होंगे तो उन्हें अध्यक्ष होंगे एवं कुम्हारों के अनुसंधान में विश्वविद्यालय के शिक्षण समाराह की अध्यक्षता करेंगे।
		(3) यदि अध्यापक की मृत्यु हो तो उनके ही प्रमुख पर शिक्षण के अधीनस्थ अन्य अधिकारों की प्रदान हो में प्रमुख अध्यापक द्वारा अनुसंधान है तो वह उनकी कार्यवाही कर सकते हैं और इस प्रकार
		(4) यदि किसी भी समय प्रमुख शिक्षण के अध्यापक और अन्य शिक्षण के अध्यापक

		<p>तत्पश्चात् न्याय करने के पश्चात् ऐसी स्थिति उत्पन्न हो कि अध्यक्ष को यह पत्र देने के लिये विश्वविद्यालय के प्रमुख से मिले। प्रमुख द्वारा धर्मनिरपेक्षता के सिद्धि प्राप्तियों के तहत अध्यक्ष को अपना पद छोड़ने के लिए कहा जा सकेगा।</p> <p>परन्तु यह कि इस उपधारा के अधीन कार्यवाही करने से पूर्व अध्यक्ष को सुनवाई का अवसर प्रदान किया जावेगा।</p>
	(5)	अध्यक्ष के कार्य निम्नलिखित शर्तों पर प्रारम्भ -
	(क)	प्रमुख कोर्ट द्वारा अनुसूचित जातों के प्रतिष्ठानों, विद्यालयों, कलेजों, आदि के रूप में किसी अध्ययन या समर्थन के विरुद्ध दिये गये निर्णयों की अपील सुनने के लिए अध्यक्ष अग्रणीय निकायों में होगा।
	(ख)	विश्वविद्यालय की कोई सूचना या अभिलेख को नष्ट करने
	(ग)	इस अधिनियम की धारा 10 के उपधारा (3) के प्रावधानों के अनुसार कुलपति को नियुक्ति करना
	(घ)	इस अधिनियम की धारा 10 के उपधारा (4) के प्रावधानों के अनुसार कुलपति को हटाना तथा
	(ङ)	ऐसी अन्य शक्तियाँ जैसा कि परिशेषावली द्वारा विहित किया गया।
कुलपति	18	<p>(1) प्रमुख कोर्ट द्वारा प्रारम्भिक दायित्व प्रत्येक प्रमुख कोर्ट को कि विश्वविद्यालय के सम्पूर्ण कार्य के संचालन हेतु उत्तरदायी होगा। यह विश्वविद्यालय के प्राधिकरणों एवं अधिकारियों को भरोसा से कार्य करेगा।</p> <p>(2) कुलपति मुख्य प्रशासनिक कुर्यातों के साथ एक समन्वय में कार्य करेगा। यह विश्वविद्यालय केन्द्रीय भागों या अन्य निष्पक्ष निकायों द्वारा समस्त कार्य पर जारी दिशानिर्देशों के निर्देशों के तहत एवं अनुभव की आवश्यकताओं को पूरा करेगा।</p> <p>(3) कुलपति की नियुक्ति उपधारा (2) के अनुसार योग्यता की शर्त पूरी करने पर और परिशेषावली द्वारा विहित नियमों एवं शर्तों पर कथित द्वारा तीन वर्ष की अवधि के लिए उपधारा (4) के अन्तर्गत गठित सौज-सह-धन समिति द्वारा सन्तुष्ट 03 (तीन) व्यक्तियों के पैनल में से की जायेगी।</p> <p>परन्तु यह कि व्यवस्थापक मण्डल के अनुमोदन के अधीन कुलपति पुनर्नियुक्ति हेतु पात्र होगा।</p>

परन्तु यह और भी कि नियामक विकल्प द्वारा निर्धारित आयु प्राप्त करने पर कोई भी व्यक्ति कुलपति नियुक्ति नहीं किया जायेगा अथवा यह धाराएं नहीं करेगा।

(4) उपधारा (3) में निर्दिष्ट समिति में निम्नलिखित व्यक्ति होंगे अर्थात् -

(क) कुलपति द्वारा नामनिर्दिष्ट 01 (एक) सदस्य

(ख) अध्यक्ष द्वारा नामनिर्दिष्ट 01 (एक) सदस्य

(ग) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा नामनिर्दिष्ट 01 (एक) सदस्य

(घ) प्रमुख सचिव/सचिव उच्च शिक्षा विभाग उत्तराखण्ड शासन

(ङ) व्यवस्थापक मण्डल द्वारा नामनिर्दिष्ट 02 (दो) सदस्य जिनमें से 01 (एक) को व्यवस्थापक मण्डल द्वारा समेत का सहायक के रूप में नामनिर्दिष्ट किया जायेगा।

(5) उपधारा (4) के अन्तर्गत गठित समिति, संश्लेषण के आधार पर कुलपति का पद धारण करने के लिए उपयुक्त तीन व्यक्तियों के नामों का पैनल तैयार करेगी और प्रत्येक ऐसे व्यक्ति की शैक्षणिक योग्यताओं तथा अन्य विशेषताओं का दस्तावेज एक संक्षेप विवरण के साथ उसे अध्यक्ष को अस्तित्वित करेगी।

परन्तु यह कि यदि खोज-तह-योजन समिति द्वारा सशुक्ति किया गया पैनल है यदि अध्यक्ष सन्तुष्ट/सहमत नहीं है तो वह अस्तित्वित का कारण देते हुए केवल एक और बार नया पैनल की मांग करवायेगा।

(6) यदि किसी समय प्राचार्यद्वारा के द्वारा या अन्यथा ऐसी जाय के उतराने जैसा कि आवश्यक हो परिस्थितियों की आवश्यकतानुसार यह स्पष्ट हो जाता है कि कुलपति के कार्यकाल की निरन्तरता विश्वविद्यालय के हित में नहीं है, तो अध्यक्ष कारण बताते हुए लिखित आदेश द्वारा आदेश में निर्दिष्ट तिथि पर कुलपति को अपना कामालय त्यागने को कह सकता है।

परन्तु यह कि इस उपधारा के अधीन कोई कार्यवाई करने से पूर्व कुलपति को सुनवाई का एक अवसर दिया जायेगा।

कुलपति की शक्तियाँ एवं शर्तियाँ

19

(1)

कुलपति विश्वविद्यालय का प्रमुख शैक्षणिक अधिकारी एवं कार्यपालक होंगे जो विश्वविद्यालय एवं इनके संघटक महाविद्यालयों/सहायकों/विद्यालयों के कार्यकलाप पर सामान्य पर्यवेक्षण और नियंत्रण रखेंगे, यह -

(क) कुलपति एव अध्यक्ष को अनुपस्थिति में विवरितानुय हो हीन
सम सही अध्यापन करेगा

(ख) अध्यक्ष तथा विवरितानुय को प्राधिकरणों के निर्देशों का
कार्यवाही करेगा

(ग) प्रधान मन्त्री तथा परिषद एवं विवरितानुय का सदन अध्यक्ष
होगा

(घ) विवरितानुय परिषदमा 03. 03. 2024 निर्देशों एवं निर्देशों के उपरान्त
का अनुपालन सुनिश्चित करेगा

(ङ) समुचित प्रशासन, सम्पत्ति, निधियों के उपयोग, समय पर परीक्षा
का आयोजन तथा परीक्षाओं की प्राप्ति तथा विश्वविद्यालय में
समुदाय बनाने रखने हेतु उत्तरदायी होगा तथा

(च) विश्वविद्यालय के विरुद्ध अन्य प्राधिकरण के निर्देशों के अन्तर्गत में
होने पर अन्यथा प्रतिभाग करने का अधिकारी होगा परन्तु इस
सम्बन्ध में अधिकार में मतदान करने हेतु अधिकृत नहीं होगा

(2) कुलपति की शक्त में विरुद्ध में प्रकरण पर निर्णय हेतु इस अधिनियम
के अन्तर्गत शक्तिमा अन्तर्गत निर्देशों के अधीन विरुद्ध प्राधिकरण को प्रदान
है पर तत्काल कार्रवाई करना आवश्यक है तो वह ऐसी कार्रवाई कर
सकता है जो वह उचित समझे तथा तत्पश्चात् विवरितानुय प्रकरण पर
अपनी कार्रवाई की कार्रवाई ऐसे अधिकारी या प्राधिकरण का होगा जो
साधारण क्रम में इस प्रकरण पर कार्रवाई करता

परन्तु यह कि यदि साधारण अधिकारी या प्राधिकरण की शक्त में
कुलपति द्वारा ऐसा कार्रवाई नहीं की जाती चाहिए थी तो अन्याय प्रमाणित
हो ऐसा निर्णय सर्वोच्च न्यायालय जाने या राज्यान्त में आने की शक्ति से 03
दो माह की अवधि में भीतर अवस्था के समान अपील दाखल करने का
अधिकार होगा, जिस पर अन्तर्गत का निर्णय अंतिम होगा।

(3) कुलपति ऐसी अन्य शक्तियों का प्रयोग करेगा और ऐसी अन्य कर्तव्यों का
अनुपालन करेगा जैसा कि परिषदमा द्वारा विहित किया जाएगा या
व्यवस्थापक मन्त्री या अध्यक्ष द्वारा अनुरोधित की जाये।

प्रति-कुलपति 20

(1) विवरितानुय के निर्देशों अन्तर्गत द्वारा कुलपति के अनुपस्थिति में निर्देशों
द्वारा निर्देश दिये हो की जायेगी और वह ऐसी कार्रवायों का प्रयोग करेगा
और ऐसी कृत्यों का सम्पादन करेगा जैसा कि परिषदमा द्वारा विहित
किया जाये या अध्यापकों और विवरितानुय में उपस्थित किया जाए

		(2)	उपपन्ना (1) के अधीन नियुक्त प्रति कुलपति आचार्य के रूप में अपने कर्तव्यों के अतिरिक्त कर्तव्यों का निर्वहन करेगा।
		(3)	प्रति कुलपति और और जब कुलपति द्वारा अर्पण की जाए, दिन प्रतिदिन के कर्तव्यों के निर्वहन करने में कुलपति की सहायता करेगा।
सकायाध्यक्ष/ प्राचार्य/ निदेशक	21		विश्वविद्यालय के प्रत्येक राज्या/राष्ट्रक/महाविद्यालय/संस्थान/विद्यालय हेतु सकायाध्यक्ष/प्राचार्य/निदेशक की नियुक्ति की प्रक्रिया ऐसी होगी एवं वह ऐसी सभी शक्तियों का प्रयोग व ऐसे सभी कर्तव्यों का अनुपालन करेगा जैसा कि परिनिषमों द्वारा विहित किया जाय।
कुलसचिव	22	(1)	कुलसचिव विश्वविद्यालय का एक पूर्णकालिक दायित्वपूर्ण अधिकारी होगा और अध्यक्ष द्वारा ऐसी शक्ति से एवं ऐसे नियमों और शर्तों पर नियुक्त किया जायेगा जैसा परिनिषमों द्वारा विहित किया जाये।
		(2)	कुलसचिव अपने पद के कारण जन्मजन्म सम्बन्ध एवं विद्या परिषद का सदस्य सचिव एवं अध्यापकों की वृत्त समिति का सदस्य और वह दत्त संस्थान तथा अन्य सामाजिक या निवासी, जैसा कि संविधानों एवं अध्यापकों द्वारा विहित हो का सदस्य होगा।
		(3)	कुलसचिव विश्वविद्यालय के अभिलेखों सम्पत्ति और सामान्य गोदार् की संग्रहित अभिरक्षा हेतु उत्तरदायी होगा तथा उसे विश्वविद्यालय के अभिलेखों को प्रमाणित करने की शक्ति होगी।
		(4)	कुलसचिव को विश्वविद्यालय की ओर से किसी सदस्य को जमाने व दस्तावेजों की हस्ताक्षरित करने की शक्ति होगी।
		(5)	कुलसचिव ऐसी समस्त दायित्वपूर्ण कार्यों के समस्त रखने के लिए कार्य होगा जो उनकी सहायता के लिए आवश्यक ह। वह ऐसी शक्तियों का प्रयोग व ऐसे कृत्यों को करेगा जैसा कि परिनिषमों अध्यादेशों और विनिषमों द्वारा विहित किया जाय या कुलपति तथा अन्य प्राधिकरणों द्वारा समय-समय पर ध्यायीकृत किया जाय।
दत्त अधिकारी	23	(1)	दत्त अधिकारी की नियुक्ति ऐसी शक्ति से की जायेगी और वह ऐसी शक्तियों का प्रयोग करेगा और ऐसे कृत्यों का सम्पादन करेगा जैसा कि विहित किया जाय।
		(2)	दत्त अधिकारी दत्त समिति का पटेल सचिव होगा।
परीक्षा नियमक	24	(1)	परीक्षा नियमक की नियुक्ति ऐसी शक्ति से की जायेगी और वह ऐसी शक्तियों का प्रयोग करेगा और ऐसे कृत्यों का सम्पादन करेगा जैसा कि परिनिषमों अध्यादेशों तथा विनिषमों द्वारा विहित किया जाय।

(2) परीक्षा नियन्त्रक परीक्षा मण्डल का सदस्य लचिव होगा।

अन्य अधिकारी 25 विश्वविद्यालय के अन्य अधिकारियों के नियुक्ति के प्रक्रिया सेव की निम्नान्न व सार शक्तिया व कसबदेरी होगे और कि परिनेयन द्वारा दिहेत किया जय

अध्याय -5
विश्वविद्यालय के प्राधिकरण

विश्वविद्यालय के प्राधिकरण	26	विश्वविद्यालय के प्राधिकरण निम्नलिखित हगे, अर्थात् -
		(क) व्यवस्थापक मण्डल
		(ख) प्रबन्धन मण्डल
		(ग) शिक्षा परिषद्
		(घ) परीक्षा मण्डल
		(ङ) पाठ्यक्रम मण्डल
		(च) योजना मण्डल
		(छ) विश्व सम्पत्ति तथा
		(ज) ऐत अन्य प्राधिकरण जो परिनेयनो द्वारा विश्वविद्यालय के प्राधिकरण घोषित किये जाए।
व्यवस्थापक मण्डल	27	(1) व्यवस्थापक मण्डल विश्वविद्यालय का मुख्य प्रशासनिक प्राधिकरण होगा जो कि परिनेयनो अध्यादेशो या विनियमो द्वारा विहित शक्तियो के प्रयोग से इसके कार्यकलापों को नियत्रित करेगा।
		(2) विश्वविद्यालय के व्यवस्थापक मण्डल में निम्नलिखित हगे-
		(क) अध्यक्ष अध्यक्ष
		(ख) कुलपति -सदस्य सचिव,
		(ग) कुलपति द्वारा नामनिर्दिष्ट प्रतिष्ठित दो शिक्षाविद्,
		(घ) राज्य सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट प्रतिष्ठित दो शिक्षाविद्,
		(ङ) प्रमुख सचिव/ सचिव उच्च शिक्षा विभाग उत्तराखण्ड ससन या उनके द्वारा नामनिर्दिष्ट व्यक्ति जो अपर सचिव सार से न्यून न हो
		(च) अध्यक्ष द्वारा प्ररसन/डीपॉरिट/प्रबन्धन/सूचना तकनीकी (आईटी) आदि क्षेत्रो से नामनिर्दिष्ट प्रतिष्ठित 03 (तीन) व्यक्ति, एवं

		(ट)	ऐसे नियम लेना व ऐसे कदम उठाना, जो विश्वविद्यालय के विद्यार्थी व उद्देश्यों के प्रभावी ढंग से निष्पादन के लिए प्रासंगिक होंगे और
		(ड)	ऐसे अन्य कृत्य को करना जैसे विहित किया जाव।
प्रबन्धन मण्डल	28.	(1)	प्रबन्धन मण्डल विश्वविद्यालय का प्रमुख कार्यपालक प्राधिकरण होगा।
		(2)	प्रबन्धन मण्डल में निम्नलिखित होंगे, अर्थात्,
		(क)	कुलपति अध्यक्ष,
		(ख)	प्रति कुसर्पति यदि कोई हो।
		(ग)	प्रायोगिक विकास द्वारा विभिन्न क्षेत्रों से नामनिर्दिष्ट 05 (पंच) दिशिष्ट व्यक्ति,
		(घ)	प्रमुख सचिव/सचिव उच्च शिक्षा विभाग उत्तराखण्ड शासन या उनके द्वारा नामनिर्दिष्ट व्यक्ति जो अपर सचिव स्तर से न्यून न हों।
		(ङ)	अध्यापक द्वारा प्रकीर्ण आधार पर नामनिर्दिष्ट अधिकाधिक 03 (तीन) संकायाध्यक्ष/प्राचार्य/निदेशक,
		(च)	अध्यापक द्वारा कुलपति की संस्तुति पर ज्येष्ठता व दर्जाक्रम से नामनिर्दिष्ट दो अध्यापक
		(छ)	वित्त अधिकारी तथा
		(ज)	कुलसचिव -सदस्य सचिव।
		(2)	प्रबन्धन मण्डल की बैठक इस प्रकार आयोजित की जायेगी जैसे कि विहित किया जाव।
		(3)	प्रबन्धन मण्डल ऐसी शक्तियों का प्रयोग करेगा एवं ऐसे कर्तव्यों का निष्पादन करेगा जैसा परिनिधियों द्वारा विहित किया जाव।
विद्या परिषद	29.	(1)	विद्या परिषद विश्वविद्यालय की प्रमुख संचालित प्राधिकरण होगी, जहाँ परिनिधियों अध्यापकों तथा शिक्षकों के उपस्थिति के अधीन रहते हुए विश्वविद्यालय की शैक्षणिक नीतियों का निर्धारण समन्वय और सन्तुष्टि पर्यवेक्षण करेगी।
		(2)	विद्या परिषद का गठन उसके सदस्यों की संख्याओं और उनकी शक्तियों और कृत्य ऐसे होंगे जैसे परिनिधियों द्वारा विहित किये जाव।

परिक्षा मण्डल	30	परिक्षा मण्डल का गठन इसकी शक्तियाँ एवं कार्य ऐसे होंगे जैसा कि परिनिधियों अध्यादेशों अथवा विनियमों द्वारा विहित किया जाय।
पाठ्यक्रम मण्डल	31	पाठ्यक्रम मण्डल का गठन इसकी शक्तियाँ एवं कार्य ऐसे होंगे जैसा कि परिनिधियों द्वारा विहित किया जाय।
योजना मण्डल	32	(1) योजना मण्डल विश्वविद्यालय का प्रमुख नियोजन प्राधिकारण होगा जो यह सुनिश्चित करेगा कि आवश्यकता और शैक्षणिक सहायता प्रणाली विश्वविद्यालय अनुदान आयोग या अन्य नियामक निकायों के प्रतिमानों को पूरा करे। (2) योजना मण्डल का गठन इनके सदस्यों की पदावधि और उसकी शक्तियाँ एवं कार्य ऐसे होंगे जैसा कि परिनिधियों द्वारा विहित किया जाय।
वित्त समिति	33	(1) वित्त समिति वित्तीय मामलों के नीचे निर्धारण व प्रबंधन हेतु विश्वविद्यालय की प्रधान वित्तीय प्राधिकरण होगी। (2) वित्त समिति का गठन उसकी शक्तियाँ और कृत्य ऐसे होंगे जैसा कि परिनिधियों द्वारा विहित किया जाय।
विश्वविद्यालय के अन्य प्राधिकरण	34	परिनिधियों द्वारा घोषित विश्वविद्यालय के अन्य प्राधिकरण का गठन शक्तियाँ एवं कृत्य ऐसे होंगे जैसा कि विहित किया जाय।
प्राधिकरण या निकाय के सदस्यों हेतु अनर्हता	35	(1) ऐसा व्यक्ति विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकरण या मंडल का सदस्य होने से अनर्ह होगा यदि वह— (क) मानसिक रूप से अशक्त है, और किसी शासन विधिकरण बोर्ड द्वारा ऐसा घोषित किया गया हो। (ख) अनुसूक्त विद्यमान है। (ग) जिसके अभावता से अन्यायित किसी अपराध के लिए सिद्ध दोष प्रकराया गया है। (घ) कहीं भी किसी परीक्षा के मसाले में किसी रूप में अनुचित आचरण का बहादा देने में अथवा उसमें विप्लव होना उसका सर्वप्रथम करने के लिये दण्डित किया गया हो। (ङ) गैरानुचित या किसी अन्य अधिकृत प्रवृत्तियों के लिये विश्वविद्यालय से किसी अन्य लाभ का उद्देश्य हो तथा (च) विश्वविद्यालय के विधि अपने व्यक्तिगत उपयोग के लिये उपयुक्त करता हो।

अध्याय -8
परिनियम, अध्यादेश एवं विनियम

परिनियम बनाने की शक्ति	35	(1)	इस अधिनियम के अधीन निर्माणाधीन तथा स्थापित विश्वविद्यालयों के प्रथम व संशोधित परिनियमों को प्रबन्धन नग्डल की संस्तुति पर व्यवस्थापक नग्डल द्वारा बनाया जायेगा और परिनियमों की राज्य सरकार के समक्ष अनुमोदन हेतु प्रस्तुत किया जायेगा।
		(2)	परिनियमों के प्राप्ति के तीन माह की अवधि के अन्दर राज्य सरकार परिनियमों पर विचार कर उन्हें अनुमोदित करेगी अथवा अपने सुझावों के साथ संशोधन हेतु विश्वविद्यालय को लौटायेगी।
		(3)	इस अधिनियम के प्रवधानों के अधीन रहते हुए परिनियमों में निम्न सभी या कोई दिव्य उपबन्धित किए जा सकेंगे अर्थात्—
		(क)	विश्वविद्यालयों के प्राधिकरण या जैसा कि समय-समय पर गठित किये जाएं, का गठन उनकी शक्तियाँ और कृत्य
		(ख)	प्राधिकरण की सदस्यों के पद पर नियुक्ति और निस्तारण प्राधिकरणों के रिक्त पदों को भरा जाना एवं प्राधिकरणों से सम्बन्धित अन्य सभी मामलों जिनके लिए ऐसा उपबन्ध करना आवश्यक होगा।
		(ग)	विश्वविद्यालय के अधिकारियों की नियुक्ति शक्ति और कर्तव्य तथा उनकी परिलब्धियाँ
		(घ)	विश्वविद्यालय के अध्यापकों अथवा शैक्षणिक प्रशासनिक एवं शिक्षण-कार्यकारी की नियुक्ति और उनकी परिलब्धियाँ
		(ङ)	विश्वविद्यालय या संस्था में कार्यरत अध्यापकों और अन्य शैक्षणिक एवं प्रशासनिक कार्यकारी की एक संयुक्त परिषद् का इच्छित गठन करने के लिए विनिर्दिष्ट अवधि के लिए नियुक्ति
		(च)	कर्मचारियों की सेवा शर्तों जिनमें सेवानिवृत्ति प्रत्युत्तर लाभ दीमा और मरिच्य निधि उनकी सेवा सम्पादन की शर्त और अनुशासनसम्पक कार्यवाही
		(छ)	कर्मचारियों की सेवा की ज्येष्ठता की शक्ति करने वाले विधान
		(ज)	विश्वविद्यालय व इसके अधिकारियों शिक्षकों, कर्मचारियों या छात्रों के कथ विवादों के निस्तारण की प्रक्रिया

	(अ) अध्यापक/लिपि छात्रपुस्तिका विद्यापुस्तिका, पदवी और पुरस्कारों को समीक्षा करने एवं प्रदान करने हेतु कक्षा निर्धारित करना
	(अ) विद्यापुस्तिका के किसी अध्यापक या छात्रपुस्तिका के विषय में 'वेब' कार्यकारी या अन्य द्वारा अवलोकन करने की क्षमता का उत्तम निस्तारण
	(क) प्रत्येक उपपरीक्षा का प्रदान किया जाना
	(ग) न्याय, विचार, समानता और अन्य विद्या सम्बन्धी विशेषताओं का वापस लेना या निस्तार करना
	(घ) स्थायी विचारों में विचार समानता में और विचारों में सहायता
	(उ) विचारों का सृजन विचारों तथा सम्बन्ध
	(अ) छात्र और कार्यकारी के साथ अनुसंधान का अनुसंधान
	(क) नदी का सृजन और सम्बन्ध
	(अ) विद्यापुस्तिका में विचारों/सम्बन्धों की प्रतिक्रियाओं
	(द) अन्य सभी विचार जो इस अध्यापक के अनुसार हो या विचार किये जायें।
	(क) प्रत्येक सम्बन्ध विद्यापुस्तिका के किसी अध्यापक की शक्तियों का उत्तम सृजन को प्रभावित करने वाला कोई ऐसा दोषविषय न हो सहायता और न ही इसमें सम्बन्ध या निस्तार करेगा जब तक कि ऐसे प्रभावों का प्रभावित प्रभावों न हो विचारों में सहायता करने का अवसर न दिया जाय और इस प्रकार छात्रों को नहीं किसी रूप में प्रभावित सम्बन्ध द्वारा विचार किये जायें।

अध्यापक की शक्ति

37 इस अध्यापक और कार्यकारी के सम्बन्धों में अध्यापक को अध्यापक सम्बन्ध का उत्तम सृजन जायें जिसमें विचारों/सम्बन्धों का उत्तम सृजन विचारों के लिए सम्बन्ध किये जा सकेंगे, अर्थात् -

	(क) विद्यापुस्तिका में छात्रों का प्रवेश और इस रूप में उनका सम्बन्ध
	(ख) विद्यापुस्तिका के सभी उपपरीक्षा विचारों एवं प्रभावों को विचारों का निर्धारण
	(ग) विचारों तथा परीक्षा का सम्बन्ध

		(घ)	उपाधि डिग्रियों का प्रमाण-पत्र और अन्य शैक्षणिक विहितियों प्रदान करना और उन्हें प्रदान या प्राप्त किए जाने हेतु अर्हताएं व उपाय निर्धारित करना।
		(ङ)	विश्वविद्यालय के अध्ययन पाठ्यक्रमों हेतु लिखे जाने वाले शिक्षण सुक्त तथा परीक्षाओं में प्रवेश उपाधि के डिग्रियों और प्रमाण-पत्रों हेतु प्रमाण सुक्त का निर्धारण।
		(च)	अध्ययनवृत्तियों, छात्रवृत्तियों विद्यार्थियों पदकों और पारितोषिकों का प्रदान करने की शक्ति।
		(छ)	परीक्षाओं का संचालन जिसके अन्तर्गत परीक्षा समिति परीक्षाओं निरीक्षण सारणीकरण और अनुसूचकों की पदावधि और नियुक्ति की होती और कार्य भी है।
		(ज)	विश्वविद्यालय के छात्रों के निवास की शक्ति।
		(झ)	छात्रों के निवास अनुशासन और अध्ययन के लिए बनायी जाने वाली विनियम व्यवस्थाएं यदि कोई हो और उनके लिए विश्वविद्यालय के अन्तर्गत विशेष अध्ययन पाठ्यक्रमों को शिक्षित करना।
		(ञ)	ऐसे कार्यवाहियों जिनके लिए परिनिधियों में उपबन्ध किया गया हो वे भिन्न कार्यवाहियों की नियुक्ति और परितोषिकों।
		(ट)	अध्ययन केन्द्रों अध्ययन केन्द्रों अन्तर्विषयक अध्ययन विविध केन्द्रों विविध प्रयोगशालाओं और अन्य समितियों की स्थापना।
		(ठ)	अन्य विश्वविद्यालयों और संस्थाओं जिसमें व्यावसायिक निष्काय या सच भी है, के साथ सहयोग और सहसम्मिता की शक्ति।
		(ड)	किसी ऐसे अन्य निष्काय/समिति जो विश्वविद्यालय को शैक्षणिक महत्ता में सुधार के लिए आवश्यक समझा जाए का गृहण उसकी सलाह और उत्तरे कृत्य।
		(ढ)	परीक्षाओं अनुसूचकों अन्तर्विषयकों और सारणीकरणों को भुगतान किए जाने वाला प्राविश्रमिक, और
		(ण)	आधिनियम या परिनिधियों द्वारा लिखित अन्य मामले।
विनियम बनाने की शक्ति	38		विश्वविद्यालय के प्राधिकरण विश्वविद्यालय की शैक्षणिक प्रशासनिक तथा अन्य गतिविधियों के लिए ऐसे विनियम बना सकेंगे जो इस अधिनियम, परिनिधियों तथा अध्यादेशों के उपबन्धों के अन्तर्गत न हों।
परिनिधियों अध्यादेशों एवं विनियमों का प्रकाशन	39		इस अधिनियम के अर्जिन बनाए गये गये प्रत्येक परिनिधिम अध्यादेश या विनियम विश्वविद्यालय द्वारा प्रकाशित किया जाएगा और उन्हें अपनी वेबसाइट तथा पब्लिक सोमम में अपलोड किया जाएगा।

विश्वविद्यालय	40	उपरोक्त विधेयक प्रस्तुत करने या किसी अन्य प्रयोजन के लिए विश्वविद्यालय द्वारा संशोधन समिति का आयोजन परिसरों, अक्षांशों और दिनेशों में यथावहित रीति के अन्तर्गत नियमित रूप से किया जाएगा।
विश्वविद्यालय का प्रशासन	41	कार्यक्रमों के प्रारम्भ होने के पूर्व वर्ष की अवधि के भीतर विश्वविद्यालय राष्ट्रीय मूल्यवर्धन एवं प्रशासन परिषद् का प्रशासन एवं ऐसे अन्य प्रशासन जो सरकार द्वारा समय-समय पर विहित किए जायें प्राप्त करेंगे। वह ऐसे अन्य दिनेशमय नियमों जो विश्वविद्यालय द्वारा संचालित माध्यमों से सम्बन्धित हैं से भी प्रशासन/प्रशासन प्राप्त करेंगे। वह विश्वविद्यालय द्वारा प्राप्त प्रेस के सम्बन्ध में राज्य सरकार को सूचित करेंगे। विश्वविद्यालय समय-समय पर ऐसे प्रशासन का पब्लिकेशन सुनिश्चित करेंगे।
अध्याय-7 विश्वविद्यालय की निधि एवं खाते		
स्थायी विन्यास निधि	42	(1) प्रायोजक निजाम द्वारा 05 (पाँच) वर्षों की अवधि के लिए राज्य सरकार के नाम से मैदानी क्षेत्र हेतु न्यूनतम 05 (पाँच) करोड़ रुपये तथा पर्वतीय क्षेत्र हेतु 03 (तीन) करोड़ रुपये की एक स्थायी विन्यास निधि राष्ट्रीय बैंक की बैंक प्रस्तावित (गारंटी) स्थापित की जायेगी तथा समयावधि पूर्ण होने पर प्रति पाँच वर्ष के परमाणु नवीनीकृत किया जाता रहेगा तथा बैंक गारंटी में प्रति पाँच वर्ष में 25 प्रतिशत की वृद्धि की जायेगी।
		(2) स्थायी विन्यास निधि का उपयोग प्रतिवृत्ति अधिनियम के रूप में यह सुनिश्चित करने हेतु उपयोग किया जायेगा कि विश्वविद्यालय द्वारा अधिनियम के प्राधान्य का अनुसरण कर रहा है तथा इस अधिनियम के तदधीन बनाये गये परिसरों अध्यादेशों या विनियमों के उपबन्धों के अनुसार कार्य कर रहा है। विश्वविद्यालय या प्रायोजक निजाम द्वारा इस अधिनियम तदधीन बनाये गये परिसरों अध्यादेशों या विनियमों के उपबन्धों का उल्लंघन करने की दशा में राज्य सरकार के पास विन्यास निधि के किसी भाग अथवा सम्पूर्ण भाग को जफत करने की शक्ति निहित होगी।
		(3) विन्यास निधि से होने वाली आय का उपयोग विश्वविद्यालय द्वारा अतिसरचनाओं के विकास अथवा विश्वविद्यालय के आर्थिक व्यय की पूर्ति हेतु किया जा सकेगा।
सामान्य निधि	43	(1) विश्वविद्यालय एक सामान्य निधि स्थापित करेगी जिसमें निम्नलिखित धनराशि जमा की जायेगी, अर्थात्— (क) समस्त शुल्क जो विश्वविद्यालय द्वारा उधारित किये जायेंगे (ख) किसी अन्य स्त्रोतों से प्राप्त समस्त धनराशि (ग) प्रायोजक निजाम द्वारा किये गये सभी अंशदान, और

		(1) किसी अन्य व्यक्ति या निकाय को हस्तागत करने किन्ती अन्य विधि द्वारा प्राधिकृत न हो द्वारा इस विधित किये गये हकी अस्तित्व।
		(2) समान्य विधि में जमा धनराशि का उपयोग विश्वविद्यालय के विकास एवं इसकी सुधारत साधनन हेतु व्यय की पूर्ति क अिये किया जायेगा।
विकास विधि	44	विश्वविद्यालय एक विन्यास विधि की स्थापना करेगा किन्ने विनियमित धनराशि जमा की जायेगी, अर्थात्:-
		(क) विकास शुल्क को छात्रों से वसूलित किये जा सकते।
		(ख) विश्वविद्यालय के विकास के प्रायोजनों हेतु अन्य स्त्रोत से प्राप्त की गयी समस्त धनराशि।
		(ग) प्रायोजक निकाय द्वारा शिर्षों गये हकी अस्तित्व।
		(4) किसी अन्य व्यक्ति या निकाय को हस्तागत करने किन्ती अन्य विधि द्वारा प्राधिकृत न हो द्वारा इस विधित किये गये हकी अस्तित्व, तथा
		(5) स्थायी विन्यास विधि में प्राप्त समस्त आय।
		(3) निम्नलिखित विधि में समग्र-समग्र पर जमा की गयी धनराशि का उपयोग विश्वविद्यालय के विकास के लिये किया जायेगा।
विश्वविद्यालय का अनुसन्ध	45	विश्वविद्यालय के प्रदान स्थापना हकी विनियमित व्यवस्थापक मण्डल को समान्य न्यवेदन और निवेदन के अधीनत तथा दिवत रीति से दिनिचयित और अनुसन्ध की जायेगी।
वार्षिक प्रतिवेदन	46	(1) विश्वविद्यालय का वार्षिक प्रतिवेदन प्रथम मण्डल के निर्देश के आधारे तैयार किया जायेगा तथा उसे ऐसे दिनांक का जस्त विहित किया जाए व्यवस्थापक मण्डल को प्रस्तुत किया जायेगा। व्यवस्थापक मण्डल अपनी वार्षिक बैठक में प्रतिवेदन पर विचार कर उसे अनुमोदित करेगा।
		(2) अनुमोदित वार्षिक प्रतिवेदन को प्रत्येक वर्ष 31 दिसम्बर से पूर्व कुलपति व राज्य सरकार के समक्ष प्रस्तुत किया जायेगा।
वार्षिक लेखा परीक्षा	47	(1) विनियमित एवं वार्षिक लेखा और तुलन-पत्र प्रवन्धन मण्डल के निर्देश के अधीन तैयार किए जाएंगे और उनकी स्वी-परीक्षा प्रवन्धन घाटेंद एकाउण्ट की अह कार्य द्वारा प्रत्येक वर्ष काम से अय एक बार और पन्द्रह माह से अनधिक के अन्तराल पर करायी जाएगी।
		(2) वार्षिक लेखा प्रतिवेदन सहित वार्षिक लेखाओं व तुलन-पत्र की एक प्रति प्रवन्धन मण्डल के प्रेषण को साथ अथवा तथा व्यवस्थापक मण्डल को वार्षिक बैठक में दिनिचयित प्रस्तुत की जायेगी।

		(3) व्यवस्थापक मण्डल अपनी कार्यवाही के लिए लेख में प्राधिकारित वित्त परीक्षा प्रतिवेदन पर विचार करके उसे अनुमोदित करेगा, व्यवस्थापक मण्डल द्वारा प्राधिकृत लेखाजी पर किए गए प्रश्न यदि कोई हों, प्रबंधन मण्डल के नज़रान में लाए जायेंगे। ऐसा प्रश्न यदि कोई हो पर प्रबंधन मण्डल द्वारा पुनरीक्षण किए जाने के पश्चात् लेख प्रतिवेदन को अध्यक्ष के अनुमोदन पर प्रस्तुत किया जायेगा।
		(4) व्यवस्थापक मण्डल द्वारा विवेचित अनुमोदित वार्षिक लेख तथा प्रबंधन की प्रति प्रत्येक वर्ष 31 दिसम्बर से पूर्व कुलमध्य एवं राज्य सरकार को गौष्ठ कराने तथा सम्बन्धित विभाग की वेब साइट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित की जायेगी।
		(5) विश्वविद्यालय के छात्रों तथा लेख परीक्षा आयोजन से सम्बन्धित दिवसों पर राज्य सरकार द्वारा दिए गए निर्देश विश्वविद्यालय पर बाध्यकारी होंगे।

विश्वविद्यालय
संविधानिक
होगा

42 विश्वविद्यालय राज्य सरकार या राज्य सरकार के तत्समिच्छीन द्वारा दिए जायेंगे जैसी अन्य निम्न अधिकांश से 'केवल' सहायता अनुदान अथवा किसी किसी सहायता का हकदार नहीं होगा।

परन्तु यह कि विश्वविद्यालय ऐसे किसी भी अनुदान को प्राप्त करने का हकदार होगा जो कि राज्य, केंद्र सरकार द्वारा या राज्य/केंद्र सरकार या संघीय या विच्छेदित अन्य निम्न या निम्न द्वारा संयोजित विधायी योजना से अनुदान इस तरह की अनुदान की रूप से अधीन दिया जाय।

अध्याय-5

राज्य सरकार व नियामक निकायों की भूमिका

विश्वविद्यालय द्वारा नियामक निकायों के नियम विनियमन मानक कांटे का अनुदान सूचना और अभिलेखों की संग्रह करने के लिए राज्य सरकार की सहिता	48	इस अधिनियम में किसी बात के होते हुए भी विश्वविद्यालय द्वारा सरकार से नियामक निकायों के सभी नियम अधिनियम मानक आदि का पालन करने के लिए बाध्य होगा और उन्हें ऐसे सभी सुविधायी एवं सहायता प्रदान करेगा जिसकी उन्हें अपने कर्तव्य के निर्वाह एवं कार्य करने में लिए आवश्यक हो।
	50	विश्वविद्यालय अथवा विश्वविद्यालय के किसी अधिकारी या अधिकारी का यह काम होगा कि वह विश्वविद्यालय के प्रशासन अथवा विनियमन और अन्य मामलों या किष्कलताओं आदि से सम्बन्धित सूचना या अभिलेखों को प्रस्तुत करेगा कि राज्य सरकार द्वारा मांग की जाय।

राज्य सरकार एवं नियामक निकायों की सुविधा	51	<p>(1) विश्वविद्यालय एक स्वायत्त निकाय के रूप में राज्य सरकार के छात्रों के अंतर्गत रूपरेखा के अंतर्गत और नियामक निकायों के विनियमों एक दिशा निर्देशों के अनुरूप कार्य करेगा। राज्य सरकार तथा नियामक निकायों की प्रतिक्रिया यह सुनिश्चित करने की रहेगी कि विश्वविद्यालय भवन व अन्य परिसरों अध्यापकों और विनियमों के सुपबन्धों के अनुरूप कार्य कर तथा शैक्षणिक हितों के सम्मानार्थक सम्पन्न हों। राज्य सरकार और नियामक निकाय अग्रोपेक्ष निरीक्षण करेगा हस्तक्षेप कर सकेगा।</p> <p>(2) राज्य सरकार समय-समय पर विश्वविद्यालय को नैतिक विनियम मान्यता हेतु निर्देश जैसा वह आवश्यक समझे जारी कर सकेगा जो इस अधिनियम के प्रावधानों से अलग न हो। ऐसे निर्देशों का अनुपालन विश्वविद्यालय द्वारा किया जायेगा जिससे टिफ्ट होने पर राज्य सरकार इस अधिनियम के अनुसार विश्वविद्यालय के विरुद्ध मुकदमा करवाह कर सकेगी।</p> <p>(3) यदि कुलपति अन्तर्गत निर्देशों का कट्टर या दुर्निष्ठाता से मानीर दुर्नियोग विश्वविद्यालय के सदस्यों की प्रति में विकलता या अन्य प्रकार के व्यवहारों और इस अधिनियम की किसी धारा के प्रावधानों का गैर अनुपालन का अभिमान होने पर राज्य सरकार जादिस जारी कर विश्वविद्यालय को 02 (दो) माह के भीतर कारवा बताने का करेगी।</p> <p>(4) उपधारा (3) के अन्तर्गत जारी निर्देशों पर विश्वविद्यालय के प्रमुख से यदि राज्य सरकार सन्तुष्ट है कि विश्वविद्यालय द्वारा इस अधिनियम के प्रावधानों के किसी भी प्रावधान का उल्लंघन किया गया है तो वह ऐसी आदेश कर सकेगी जैसा वह समझे।</p> <p>(5) यदि उपधारा (4) के अंतर्गत जारी निर्देशों के अन्तर्गत प्राप्त होने पर राज्य सरकार सन्तुष्ट है कि विश्वविद्यालय द्वारा इस अधिनियम के प्रावधानों के किसी भी प्रावधान का उल्लंघन किया गया है तो वह विश्वविद्यालय पर सख्त लगाये नियामक निकायों का विश्वविद्यालय की मान्यता समाप्त करने की सन्तुति अथवा विश्वविद्यालय के परिसरों को लॉक करने का निर्देश कर सकेगा।</p> <p>(6) राज्य सरकार को दुर्निष्ठाता के दिना विश्वविद्यालय के किसी अधिकारी का उन्मोचन द्वारा विश्वविद्यालय को किसी भी अवधि सम्पत्ति को निरस्त करने के अधिकार के सम्मानार्थक नहीं किया जा सकेगा।</p>
शुल्क	52	<p>(1) प्रत्येक वर्ष के अन्तर्गत प्रयोजनों हेतु शुल्क संग्रहण का विनियम विश्वविद्यालय के व्यवस्थापक मंडल द्वारा गठित एक शुल्क निर्धारण समिति की सन्तुति पर किया जाएगा। शुल्क निर्धारण समिति में प्रत्येक बजट विद्या परिषद् से लिए गए सदस्यों के साथ कार्यक्रम और नैतिक से सम्बन्धित ग्राह्य विशेषज्ञ सम्मिलित होंगे। प्रत्येक बजट का एक परिषद् सदस्य शुल्क निर्धारण समिति की अध्यक्षता करेगा।</p>

		(2)	प्रवेशन परीक्षा द्वारा नियत शिक्षण शुल्क निम्नलिखित 03 (तीन) श्रेणियों में से एक के लिए मान्य होगा। विश्वविद्यालय द्वारा नियत सभी शुल्क एवं प्रवेश तथा शुल्क निर्धारण की प्रक्रिया परंपरागत पूर्ण प्रत्यक्ष एवं सामाजिक होंगे। किसी भी पाठ्यक्रम के पूरा होने की अवधि के दौरान नामांकित छात्र से लिया जाने वाले शिक्षण शुल्क में कटौती नहीं की जायेगी।
		(3)	विश्वविद्यालय छात्रों से शुल्क निर्धारण सम्बन्धी अथवा नियामक निकायों द्वारा नियत शुल्क के अतिरिक्त, कंपिटेशन शुल्क आदि जैसी कोई अन्य शुल्क किसी भी रूप में नहीं लेगा और शिक्षा का ध्यायपूर्ण रूप नहीं करेगा।
		(4)	प्रदत्त किए जाने वाले पाठ्यक्रमों हेतु लिए जाने वाले शुल्क के स्तर का मातृकाओं को समझाते करने की लागत शुल्कभूत सुविधाओं, शिक्षण व शोध की गुणवत्ता और अन्य सुविधाओं के साथ एक उचित सम्बन्ध होना चाहिए। किसी भी पाठ्यक्रम और सत्र में प्रवेश प्रारम्भ करने से पूर्व प्रवेश प्रक्रिया एवं शुल्क सत्यापन को विश्वविद्यालय की विश्वसनीयता में प्रभावित किया जाएगा और विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर अपलोड करना अनिवार्य होगा।
		(5)	विश्वविद्यालय द्वारा शुल्क निर्धारण की पूरी प्रक्रिया एवं अभिलेखों को संरक्षित रखा जाएगा और उसकी एक प्रति राज्य सरकार को सूचना हेतु एवं आवश्यकता पड़ने पर अग्रिम विचार हेतु भेजी जायेगी।
		(6)	किसी पाठ्यक्रम में नामांकित किसी छात्र द्वारा शुल्क निर्धारण के गलत होने निर्धारित एव सार्वजनिक किए गए शुल्क से अधिक शुल्क या धन को माँग से सम्बन्धित व्यवस्थापक मण्डल के समक्ष की गई किसी लिखित शिकायत के दल होने की दशा में व्यवस्थापक मण्डल या तो स्वयं अथवा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के दिनिधम की मानकानुसार गठित छात्र शिक्षण निगरान समिति के माध्यम से मामलों को निरस्तित करेगा।
		(7)	व्यवस्थापक मण्डल अथवा छात्र शिक्षण निगरान समिति से निर्देशों से अनुरोध कोई छात्र मामले को सहायक अभिलेखों के सहित विश्वविद्यालय के निधाय आन के दो माह के भीतर राज्य सरकार को सौंपित कर सकेगा।
		(8)	राज्य सरकार मामले को परीक्षण कर निर्णय लेगी और उसका निर्णय अन्तिम होगा।
कम्प्लेंट का प्रसंग	33	(9)	जो कोई भी इस अधिनियम या इसके अन्तर्गत, धरौकत के किसी मामले या प्रवेश व उपाधि प्रदत्त करने सम्बन्धी मामले या अकथन देने अथवा शुल्क से सम्बन्धित मामला या शिक्षकों की नियुक्ति के मामलों के लिए बनाए गए नियमों के प्रावधानों का उल्लंघन करेगा वह दोष सिद्ध होने पर ऐसी धरौकतों के जुर्माने से जो राज्य सरकार द्वारा राज्य समग्र पर अधिनियमित

की जाहद दण्डनीय होगी।

परन्तु यह कि उन्हें इस अधिनियम में विश्वविद्यालय की संज्ञित हो-
नी इस अधिनियम के अन्तर्गत विश्वविद्यालय सम्बन्धित करने हेतु सरकार
द्वारा प्रदत्त प्राधिकार-यत्र मापस लिया जा सकेगा।

- (2) इस अधिनियम के अधीन दण्डनीय होने पर राज्य का विद्यार्थी प्रथम श्रेणी
के मजिस्ट्रेट के न्यायालय से न्यून किसी न्यायालय द्वारा नहीं किया
जायेगा और प्रमुख साक्षर/साक्षिण उच्च शिक्षा विभाग उत्तराखण्ड सरकार
अथवा उसके द्वारा इस विधि सम्बन्धित शिक्षा आदेश द्वारा निर्दिष्ट
न प्राप्तकृत किसी अन्य व्यक्ति द्वारा शिक्षित करने पर ही एक अपराध
का समूह लिया जायेगा।
- (3) किसी अन्य अधिनियम में निर्दिष्ट दण्ड पर अतिरिक्त प्रत्येक व्यक्ति को इस
धारा के अधीन दण्ड अतिरिक्त दिया जा सकेगा।

अध्याय - 6

विश्वविद्यालय का विघटन/परिसमापन

विश्वविद्यालय
का विघटन/
परिसमापन

- (1) यदि प्रायोजक निम्नलिखित विश्वविद्यालय को विघटित करने का फैसला करता
है तो वह राज्य सरकार को कम से कम एक वर्ष पूर्व का नोटिस लिखित
रूप में देगा।
- (2) अध्याय (1) में संदर्भित नोटिस की प्राप्ति पर राज्य सरकार विश्वविद्यालय
के विघटन की तिथि से लेकर उसके विघटित प्रायोजक के प्राप्ति के
अन्तिम दंड का प्रादोषक/प्रादोषिका पूर्ण होने तक के लिए विश्वविद्यालय
के प्रशासन हेतु ऐसे व्यवस्थाएं इस प्रकार करेगी जैसी विहित की जाये।
- (3) धारा-51 की उपधारा (5) के उपबन्धों के अन्तर्गत राज्य सरकार
विश्वविद्यालय के परिसमापन का निर्णय लेती है तो इस सम्बन्ध में बनाए
गये प्रावधानों के उपबन्धों के अन्तर्गत वह विश्वविद्यालय के परिसमापन
की प्रक्रिया प्रारम्भ करेगी।

परन्तु यह कि विश्वविद्यालय के परिसमापन की आवश्यकता उत्पन्न
विशेष को अनुपपन्न का समुचित अद्वार प्रदान दिये बिना प्रारम्भ नहीं की
जायेगी।

- (4) अध्याय (2) व (3) के अधीन विश्वविद्यालय के विघटन का परिसमापन की
प्रक्रिया पूर्ण होने पर राज्य सरकार शासकीय मजल में अधिसूचना द्वारा
विश्वविद्यालय के विघटन का परिसमापन का आदेश जारी करेगी और ऐसे
अधिसूचना के प्रकाशित किये जाने के दिनांक से विश्वविद्यालय
विघटित/परिसमापन हुआ माना जायेगा और विश्वविद्यालय की सभी संप-
त्तियां एवं दस्तावेज उक्त दिनांक से प्रायोजक विभाग में स्थित हो
जायेगी।

		(5) मुल्काते के आदेश के अतनुष्ट कर्मचारी को ऐसे आदेश की सुचना का जानकारी के दो माह के भीतर अध्यक्ष के समक्ष अपील करने का अधिकार होगा जिसका निर्णय अन्तिम होगा।
		(6) इस अधिनियम में किसी बात के होते हुए भी, विश्वविद्यालय के कर्मचारियों को लोक सेवक नहीं समझा जायेगा और यह इपेता, इस अधिनियम के प्रायोजन के सिधे या अप्रत्यक्ष विश्वविद्यालय के निजी रोजगार के अधीन रहेंगे।
अपील का अधिकार	60.	विश्वविद्यालय या विश्वविद्यालय द्वारा अनुसूचित महाविद्यालय या संस्थान के प्रत्येक कर्मचारी या छात्र को इस अधिनियम में किसी बात के होते हुए भी विश्वविद्यालय के किसी अधिकारी या प्राधिकरण व्यवस्थित के विनिश्चय के विरुद्ध एक समय के भीतर जैसा परिनिर्णयों द्वारा विहित हो विश्वविद्यालय के व्यवस्थापक मण्डल के समक्ष अपील करने का अधिकार होगा और व्यवस्थापक मण्डल ऐसे विनिश्चय को जिसके विरुद्ध अपील की गयी है, पुष्ट या उपन्तारित कर सकेगा या उत्तर सकेगा।
शिकायत निवारण समिति	61.	(1) जिसकी शिक्षक-कर्मचारियों के साथ-साथ उसके विभागों के छात्रों को शिकायत पर विचार करने उन्हें सुनने और जहाँ तक सम्भव हो तीन माह के भीतर उनका निवारण करने के लिए प्रत्येक विश्वविद्यालय की एक शिक्षागत निवारण समिति होगी समिति उसके द्वारा निपटान की गई शिकायतों की अन्तर्गत आख्या प्रबन्धन मंडल को देगी। (2) शिकायत निवारण समिति का गठन, उसकी शक्ति कार्य और शिकायतों के निपटान करने हेतु अपेक्षायी जाने वाली प्रक्रिया ऐसी होगी जैसी कि परिनिर्णयों द्वारा विहित हो का नियामक निकायों के विनिश्चयों में दी गयी हो।
भविष्य निधि एवं पेंशन	62.	विश्वविद्यालय अपने कर्मचारियों के साथ के लिए जैसा उचित समझे ऐसी भविष्य निधि या पेंशन निधि में या कल्याणकारी योजनाओं का गठन करेगा और ऐसी सेवा योजना की व्यवस्था ऐसी रीति और शर्तों के अध्याधीन करेगा जैसी परिनिर्णयों द्वारा विहित की जाये।
प्राधिकरणों और निकायों के गठन सम्बन्धी विषय	63.	यदि यह प्रश्न उत्पन्न हो कि क्या कोई व्यक्ति विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकरण या अन्य निकाय के सदस्य के रूप में विधिवत नामनिर्दिष्ट या नियुक्त किया गया है या उसका सदस्य होने का हक्कदार है तो यह विषय अध्यक्ष का निर्दिष्ट किया जायेगा जिस पर उसका विनिश्चय अन्तिम होगा।
आकस्मिक रिक्तियों की पूर्ति	64.	विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकरण या अन्य निकाय की सभी आकस्मिक रिक्ति (पदेन सदस्यों या गिन्न सदस्यों) की पूर्ति प्राप्तिशील ऐसे व्यक्ति या निकाय द्वारा की जायेगी जो उस सदस्य जिसकी जगह रिक्त हुई है को नियुक्त व्यवस्थित या सहसंयोजित करता है और ऐसी आकस्मिक रिक्ति हेतु नियुक्त व्यवस्था या सहसंयोजित व्यक्ति उस अवशिष्ट अवधि के लिए सदस्य होगा, जिसके लिए वह व्यक्ति जिसका स्थान वह भरता है, सदस्य बना रहता है।

नियंत्रणों के माध्यम से प्राप्तिकरणों और भिन्नताओं की आवश्यकता का अभाव न होना	65	विश्वविद्यालय के प्राप्तिकरण व अन्य विद्यालय के गठन में किसी बुरे अध्यापक के साथ कार्य के कारण प्राप्तिकरण या भिन्नता का कोई भी कारण या प्राप्तिकरण अभाव नहीं होगी।
सम्बन्धपूर्ण है गयी कार्यवाही के द्वारा विश्वविद्यालय के अभिलेखों को प्रभावित करने की दिशि	66	विश्वविद्यालय के किसी अधिकारी या कर्मचारी के विरुद्ध कोई दण्ड या अन्य शिष्टाचार कार्यवाही किसी भी ऐसे विषय के सम्बन्ध में जारी नहीं की जा सकती। अतः इस अधिनियम या प्राप्तिकरणों या अध्यादेशों या विधियों के उपबन्धों के अन्तर्गत में सम्बन्धपूर्णता सिद्ध नहीं हो सकती जो कि किसी अन्य कानून के अन्तर्गत में विश्वविद्यालय के किसी प्राप्तिकरण या कर्मचारी को कोई दण्ड या अन्य सजा या कार्यवाही, सजा या अन्य दण्डनीयता या प्राप्तिकरण में शामिल करने के अन्तर्गत में हो कि यदि कुलनियम द्वारा प्रमाणित किट गठित हो कि इसी दण्ड अधिनियम के अन्तर्गत, सजा या अन्य दण्डनीयता या प्राप्तिकरण में प्रविष्टि की दिशा में प्रथम दृष्टया सजा के रूप में प्रमाणित किया जायेगा और उसमें अभिलेखित विषय को सम्बन्धित के लिए सजा के रूप में प्रमाणित करण किया जायेगा जैसा कि यदि मूल दण्ड प्राप्तिकरण की जाती तो दण्ड सजा के रूप में स्वीकार होती।
सरकार की नियम बनाने की शक्ति	68	सरकार इस अधिनियम के सभी अर्थों किसी उपबन्ध के विधान-वदन को लिए नियम बना सकती है।
कॉलेजों के नियंत्रण की शक्ति	69	(1) यदि इस अधिनियम के प्राप्तिकरणों को लागू करने में कोई कठिनाई उत्पन्न हो तो राज्य सरकार सलाह में प्रमाणित आदेश द्वारा ऐसे प्राप्तिकरण कर सकती जो इस अधिनियम के प्राप्तिकरणों से अभाव में हो और जो उस प्राप्तिकरण को दूर करने के लिए आवश्यक या समीचीन प्रमाणित हो। परन्तु यह कि कोई ऐसा आदेश इस अधिनियम के प्राप्तिकरण से 33 दिन के अन्तर्गत ही समाप्त हो प्रमाणित नहीं दिया जायेगा।
उत्तराखण्ड के अध्यालय में विद्यार्थी का विस्तारण अध्यापकों का प्रभाव	70	इस अधिनियम व इसके अन्तर्गत बनाये गये प्राप्तिकरणों अध्यादेशों एवं विधियों के उपबन्धों के प्रविष्टि में सम्बन्धित प्राप्तिकरण सभी विद्यार्थी का विस्तारण उत्तराखण्ड राज्य के सहित अध्यालय द्वारा किया जायेगा।
	71	इस अधिनियम व इसके अन्तर्गत बनाये गये प्राप्तिकरणों अध्यादेशों एवं विधियों के उपबन्धों का निजी विश्वविद्यालयों के सम्बन्ध में राज्य विधान सभा द्वारा सलाह प्रदान किसी विधि के प्रतिकूल होते हुए की अध्यापकों प्रभावित नहीं।

निरस्तन और धनकृति	72	<p>(1) इस अधिनियम के प्रभाव में आने के पश्चात् इस अधिनियम की अनुसूची-1 के सम्म-2 में उल्लिखित समस्त अधिनियम निरस्त हो जायेंगे।</p> <p>(2) अध्यापन, के दक्षिण अनुसूची में उल्लिखित अधिनियमों के निरस्त होते हुए भी ऐसे निरस्त अधिनियमों के अधीन स्थापित विश्वविद्यालय द्वारा किए गए सभी नियमों, कानूनों, कानूनी शक्तियों एवं सृजित समस्त दस्तावेज इस अधिनियम के अधीन मान्य समझे जायेंगे।</p> <p>(3) निरस्त अधिनियमों के उपबन्धों के अधीन बनाये गये परिचय अध्यादेश या नियम एवं विनियम इस अधिनियम के प्रावधानों के अधीन बनाये गये नये पारित्यम अध्यादेश एवं विनियमों के बनावे जाने तक प्रवर्द्ध रहेंगे।</p> <p>परन्तु यह कि निरस्त अधिनियमों के अधीन स्थापित विश्वविद्यालय जो कि अब इस अधिनियम के अधीन नियमित एवं स्थापित किये गए हैं इस अधिनियम के प्रारम्भ होने के तुरन्त से 01 (एक) वर्ष के भीतर राज्य सरकार के समक्ष अपने प्रतिनिधित्व अनुमोदन हेतु प्रेषित करेंगे।</p>
संलग्नक-2 अध्यापन	73	<p>इस अधिनियम के परिचयमों में किसी बात के होते हुए भी -</p> <p>(अ) प्राथमिक शिक्षा प्रथम अध्यापन नियुक्ति करेंगे।</p> <p>(ब) प्रथम कुलपति की नियुक्ति अध्यक्ष द्वारा ऐसी सीट एवं ऐसी शर्तों के अधीन की जायेगी, जैसा वह उचित समझे एवं कुलपति 03 (तीन) वर्ष की अवधि के लिए यह धारण करेंगे।</p> <p>(ग) प्रथम कुलपति और प्रथम शिक्षा अधिकारी की नियुक्ति अध्यक्ष द्वारा ऐसी शर्तों एवं ऐसी शर्तों के अधीन की जायेगी, जैसा वह उचित समझे एवं उक्त अधिकारी 03 (तीन) वर्ष की अवधि के लिए यह धारण करेंगे।</p> <p>(घ) प्रथम अध्यापक मजदूर का कार्यकाल 03 (तीन) वर्ष से अधिक अवधि के लिए नहीं होगा, एवं</p> <p>(ङ) अध्यक्ष द्वारा प्रथम अध्यक्ष मजदूर, प्रथम शिक्षा समिति और प्रथम शिक्षा परिषद का गठन 03 (तीन) वर्ष की अवधि के लिए किया जाएगा।</p>
अध्यक्षक नियम विश्वविद्यालय	74	<p>इस अधिनियम में उल्लिखित किसी बात के होते हुए भी उत्तराखण्ड राज्य के प्राथमिक या माध्यमिक अध्यापक द्वारा स्थापित विश्वविद्यालय भारत का संविधान के अनुच्छेद 30 द्वारा रक्षा प्राप्त विश्वविद्यालय मान्य कर रहे हैं।</p>

अनुसूची-1
स्थापित निजी विश्वविद्यालय

क्र.सं0	विश्वविद्यालय का नाम एवं मुख्य परिसर	अधिनियम का नाम	शासक निकाय
1	श्री सरस्वती विश्वविद्यालय शासकीय-मानिकपुर देहरादून-248011	श्री सरस्वती विश्वविद्यालय अधिनियम 2002 (उत्तराखण्ड अधिनियम सं0 08 सन 2002)।	श्री देवपाल गहवी ट्रस्ट, इटानगर
2	एन.एस. जी.एस.-बैंगली बंग-प्रेमनगर देहरादून-248007	एन.एस. एवं जी.एस. अधिनियम विश्वविद्यालय अधिनियम, 2003 (उत्तराखण्ड अधिनियम सं0 15 सन 2003)।	हाईवे कॉमर्स एजुकेशन एण्ड रिसर्च सोसाइटी 210 टिनीट हल ओल्ड इन्स्टीट्यूट स्ट्रीट नं0 3, आखला, नई दिल्ली, 110020
3	इरफाई विश्वविद्यालय राज बहा रोड सेक्टर 15 ठाऊन सोलापुर, देहरादून-248011	इरफाई विश्वविद्यालय अधिनियम 2003 (उत्तराखण्ड अधिनियम संख्या 16 सन 2003)।	र इरफाई सोसाइटी इटानगर सेक्टर 15
4	हिमचिनी जी. विश्वविद्यालय जी.एस. मोपु, बकला रोड, देहरादून	हिमचिनी नम विश्वविद्यालय (एन.एच.सीटी इन ए स्टाई) अधिनियम 2003 (उत्तराखण्ड अधिनियम सं0 17 सन 2003)।	तालीम रिसर्च फाउंडेशन अहमदाबाद गुजरात
5	पतञ्जलि विश्वविद्यालय पतञ्जलि ग्राम, रुड़की हरिद्वार रोड हरिद्वार।	पतञ्जलि विश्वविद्यालय अधिनियम 2006 (उत्तराखण्ड अधिनियम सं0 04 सन 2006)।	र पतञ्जलि चैतन्य (ट्रस्ट) नई दिल्ली
6	ग्रामिण एग एजुकेशन विश्वविद्यालय बेत रोड कोमलवाहन देहरादून	उत्तराखण्ड ग्रामिण एग एजुकेशन विश्वविद्यालय अधिनियम 2011 (उत्तराखण्ड अधिनियम सं0 12 सन 2011)।	ग्रामिण एग एजुकेशन सोसाइटी 504/6 बैत रोड उत्तराखण्ड टाउन देहरादून-248002
7	डी आई टी विश्वविद्यालय मसूरी डाइजैज रोड मजकवाला देहरादून-248009	डी आई टी विश्वविद्यालय अधिनियम 2012 (उत्तराखण्ड अधिनियम सं0 10 सन 2012)।	यूनिसन एजुकेशन फाउंडेशन तृतीय सतरा ब्रह्मचरिनी ब्लॉक आई एम एस यूनिसन विश्वविद्यालय ग्राम मजकवाला, उत्तराखण्ड-248009
8	आई एम एस यूनिसन विश्वविद्यालय मसूरी डाइजैज रोड नफला बाना देहरादून-248009	आई एम एस यूनिसन विश्वविद्यालय अधिनियम 2012 (उत्तराखण्ड अधिनियम सं0 13 सन 2012)।	यूनिसन एजुकेशन फाउंडेशन तृतीय सतरा ब्रह्मचरिनी ब्लॉक आई एम एस यूनिसन विश्वविद्यालय ग्राम मजकवाला, उत्तराखण्ड-248009

9	उत्तराखण्ड विश्वविद्यालय आरकौंडिया गेट चंदनबाड़ी गुप्तनगर देहरादून-248001 उत्तराखण्ड	उत्तराखण्ड विश्वविद्यालय अधिनियम 2012 (उत्तराखण्ड अधिनियम नं० 11 सन् 2013)	सुशीला देवी सेंटर फॉर जेनेसायल स्टडीज एम्ब रिसर्च भौतइटी, आरकौंडिया गेट, पोस्ट आंकरा चंदनबाड़ी, प्रेमनगर, देहरादून, उत्तराखण्ड
10	रहामी राम हिमानदन विश्वविद्यालय स्वामी राम नगर जौलीगट देहरादून-248140, उत्तराखण्ड	हिमानदन विश्वविद्यालय अधिनियम 2012 (उत्तराखण्ड अधिनियम नं० 12 सन् 2013)	हिमातदन इस्टीट्यूट इन्स्टीट्यूट ट्रस्ट, स्वामी राम नगर जौलीगट देहरादून-248061 उत्तराखण्ड
11	मदरहुड विश्वविद्यालय कलेजी मदरानपुर रुड़की (हरिद्वार, उत्तराखण्ड)	मदरहुड विश्वविद्यालय अधिनियम 2014 (उत्तराखण्ड अधिनियम नं० 05 सन् 2015)	मदरहुड इस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट टेक्नॉलॉजी सोल्सइटी राम कलेजी पोस्ट मदरानपुर रुड़की
12	भगवत ग्लोबल विश्वविद्यालय, उत्तरा अन्वर्ष चौर कोटद्वार जिला-पीली गढवाल, उत्तराखण्ड	भगवत ग्लोबल विश्वविद्यालय, अधिनियम 2016 (उत्तराखण्ड अधिनियम नं० 08 सन् 2016)	भगवत एजुकेशन कालेजिन नई दिल्ली
13	महाबाजा अदालत हिमातदन चक्रवाल विश्वविद्यालय धौद गट क्लिक पोखरा जिला पीली गढवाल 248189 उत्तराखण्ड	हिमातदन गढवाल विश्वविद्यालय, अधिनियम 2016 (उत्तराखण्ड अधिनियम नं० 13 वर्ष 2016)	जनसाधन एजुकेशनल ट्रस्ट 13 नवीन मार्ग शाहिबाबाद गढ़वेयाबाद
14	रत्न विहारी रास सुमरती विश्वविद्यालय कोटगा सपुर नर की घौडी देहरादून 248007, उत्तराखण्ड	रत्न विहारी कोट सुमरती विश्वविद्यालय अधिनियम 2016 (उत्तराखण्ड अधिनियम नं०-35 सन् 2016)	डॉ० जगत नारायण कुमरती चारटेडल ट्रस्ट, देहरादून
15	श्री गुरु राम राय विश्वविद्यालय ट्रेल पटेल नगर पटेल नगर देहरादून-248001, उत्तराखण्ड	श्री गुरु राम राय विश्वविद्यालय अधिनियम 2016 (उत्तराखण्ड अधिनियम नं० 03 वर्ष 2017)	श्री गुरु राम राय विश्व विद्या मंडलाइटी देहरादून
16	लॉरेन्स विश्वविद्यालय रुड़की-देहरादून हाइवे मदावर रुड़की-247187 उत्तराखण्ड	लॉरेन्स विश्वविद्यालय अधिनियम 2016 (उत्तराखण्ड अधिनियम नं० 04 वर्ष 2017)	एल एम डी एजुकेशनल एम्ब रिसर्च फाउन्डेशन (ट्रस्ट) 14/1 न्यू रोड देहरादून

17	श्रीधर मण्डल विर विश्वविद्यालय पूर्व छात्रावास बनारस ता. ईश्वरपुर-249141 उत्तरप्रदेश	श्रीधर मण्डल विर विश्वविद्यालय अभियोग 2018 (विश्वविद्यालय अभियोग सं. 12 तारीख 2018)	श्रीधर मण्डल विर विश्वविद्यालय अभियोग सं. 12 तारीख 2018
18	विनायक विरविद्यालय बनारस ता. ईश्वरपुर उत्तरप्रदेश	विनायक विरविद्यालय अभियोग 2018 (विश्वविद्यालय अभियोग सं. 08 तारीख 2018)	विनायक विरविद्यालय अभियोग 2018 (विश्वविद्यालय अभियोग सं. 08 तारीख 2018)
19	श्रीधर मण्डल विर बनारस ता. ईश्वरपुर उत्तरप्रदेश	श्रीधर मण्डल विर विश्वविद्यालय अभियोग 2018 (विश्वविद्यालय अभियोग सं. 12 तारीख 2018)	श्रीधर मण्डल विर विश्वविद्यालय अभियोग सं. 12 तारीख 2018
20	श्रीधर मण्डल विर बनारस ता. ईश्वरपुर उत्तरप्रदेश	श्रीधर मण्डल विर विश्वविद्यालय अभियोग 2018 (विश्वविद्यालय अभियोग सं. 12 तारीख 2018)	श्रीधर मण्डल विर विश्वविद्यालय अभियोग सं. 12 तारीख 2018
21	श्रीधर मण्डल विर बनारस ता. ईश्वरपुर उत्तरप्रदेश	श्रीधर मण्डल विर विश्वविद्यालय अभियोग 2018 (विश्वविद्यालय अभियोग सं. 12 तारीख 2018)	श्रीधर मण्डल विर विश्वविद्यालय अभियोग सं. 12 तारीख 2018
22	श्रीधर मण्डल विर बनारस ता. ईश्वरपुर उत्तरप्रदेश	श्रीधर मण्डल विर विश्वविद्यालय अभियोग 2018 (विश्वविद्यालय अभियोग सं. 12 तारीख 2018)	श्रीधर मण्डल विर विश्वविद्यालय अभियोग सं. 12 तारीख 2018

अनुसूची-2

इस अधिनियम के तहत स्थापित एवं नियमित निजी शिक्षणविद्यलय

क्र.सं.	शिक्षणविद्यलय का नाम एवं मुख्य परिचय	अधिनियम का नाम	प्रायोजक/निकाह
1			
2			
3			
4			

आज्ञा से,

राजनारायण मुहम्मद दिलवर दानिया,
अधिकांश सचिव।

उद्देश्यों और कारणों का कथन

प्रदेश ने अलग-अलग अधिनियमों द्वारा निजी विश्वविद्यालय स्थापित एवं निगमित किये गये हैं। निजी विश्वविद्यालयों के अधिनियमों में भिन्न-भिन्न उपबन्ध हैं एवं उनके अनुश्रवण हेतु कोई समान व्यवस्था नहीं है अतएव किसी एक ही दिशि के अधीन समस्त निजी विश्वविद्यालयों को शासित करने के उद्देश्य से एक अमोक्ष्य अधिनियम बनाये जाने का विनिश्चय किया गया है।

2- प्रस्तावित विधेयक उपर्युक्त उद्देश्य की पूर्ति करता है।

डा० मन सिंह रावत
मंत्री

No 02/XXXV(3)/2024/58(1)/2023
Dated Dehradun, January 03, 2024

NOTIFICATION

Miscellaneous

In pursuance of the provisions of Clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of 'The Uttarakhand Private University Act, 2023' (Act No. 02 of 2024).

As passed by the Uttarakhand Legislative Assembly and assented to by the Governor on 01st January, 2024.

THE UTTARAKHAND PRIVATE UNIVERSITIES ACT, 2023
(Uttarakhand Act No. 02 of 2024)

Index

Sections	Details	Page No
CHAPTER I		
Preliminary		
1.	Short title, Extent and Commencement	49
2.	Definitions	49-52
CHAPTER II		
Establishment of University		
3.	Condition for establishment of the University	52
4.	Submission Proposal for Establishment of the Private University	53
5.	Evaluation and recommendation of proposals	53
6.	Issuance of letter of intent and submission of compliance report by Sponsoring Body	53
7.	Establishment of the University	53-54
CHAPTER III		
Incorporation of University and its Objectives		
8.	Incorporation of Universities	54
9.	Objectives of the University	54-55
10.	Power of the University	55-57
11.	Admission and Academic Standards	57-58
12.	University to be open to all Classes and Creeds	58
13.	Provisions for Permanent Residents of the State of Uttarakhand	58
14.	No Power to Affiliate any Institution	58
CHAPTER IV		
Officers of the University		
15.	Officers of the University	58-59
16.	The Visitor	59
17.	The President	59-60
18.	The Vice-Chancellor	60-61
19.	Powers and Duties of the Vice-Chancellor	61-62
20.	The Pro-Vice-Chancellor	62
21.	Dean, Principa/Director	62
22.	The Registrar	62-63

23.	The Finance Officer	63
24.	The Controller of Examinations	63
25.	Other Officers	63
CHAPTER V		
Authorities of the University		
26.	Authorities of the University	63-64
27.	The Board of Governors	64-65
28.	The Board of Management	65-66
29.	The Academic Council	66
30.	The Board of Examinations	66
31.	The Boards of Studies	66
32.	The Planning Board	66
33.	The Finance Committee	66-67
34.	Other authorities of University	67
35.	Disqualification of the Members of an Authority or Body	67
CHAPTER VI		
Statutes, Ordinances and Regulations		
36.	Powers to make Statutes	67-69
37.	Power to make Ordinances	69-70
38.	Power to make Regulations	70
39.	Publication of Statutes, Ordinances and Regulation	70
40.	Convocation	70
41.	Accreditation of University.	70
CHAPTER VII		
Funds and Account of the University		
42.	Permanent Endowment Fund	70-71
43.	General Funds	71
44.	Development Funds	71
45.	Maintenance of Funds	71
46.	Annual Report	72
47.	Annual Account and Audit	72
48.	The University shall be self financed	72
CHAPTER VIII		
Role of State Government and Regulatory Bodies		
49.	University to follow rules, regulations, norms, etc. of regulatory bodies.	73
50.	Power of State Government to call for information and records	73
51.	Role of the Government and Regulatory Bodies	73-74

52.	Fees	75
53.	Provisions of Penalties	7
CHAPTER IX		
Dissolution Winding up of University		
54.	Dissolution Winding up of University	75-76
55.	Expenditure of the University during Dissolution Winding up	76
CHAPTER X		
Miscellaneous and Transitory Provisions		
56.	Duties of Teachers	76
57.	Obligation to perform Examination work	76
58.	Returns and information	77
59.	Conditions of service of employees, etc.	7
60.	Right to appeal	77
61.	The Grievance Redressal Committee	78
62.	Provident fund and pension	78
63.	Disputes as to jurisdiction of authorities or bodies	78
64.	Filling of actual vacancies	78
65.	Proceedings of authorities or bodies not to be invalidate due to vacancies	78
66.	Protection of action taken in good faith	78
67.	Maintenance of University records	79
68.	Powers of the Government to make rules	79
69.	Power to remove difficulties	79
70.	Disputes to be settled in a Court in Uttarakhand	79
71.	Overriding effect	79
72.	Repeal and saving	79-80
73.	Transitional provisions	80
74.	Minority Private Universities	80

THE UTTARAKHAND PRIVATE UNIVERSITIES ACT, 2023

(Uttarakhand Act No. 02 of 2024)

An

Act

to establish and incorporate new private Universities and to repeal the Acts of existing Private Universities and to incorporate them under this Act in the state of Uttarakhand, with emphasis to provide for qualitative, multidisciplinary and industry relevant Higher Education and to uniformly regulate their functions and for the matters connected therewith or incidental thereto

Be it enacted by Uttarakhand State legislative assembly in the Seventy Fourth year of Republic of India, as follows,-

CHAPTER I

Preliminary

Short title, extent and commencement	1.	(1)	This Act may be called the Uttarakhand Private Universities Act, 2023
		(2)	It shall extend to the whole of the State of Uttarakhand.
		(3)	It shall come into force on such date as the State Government may by notification in the official gazette, appoint.
Definitions	2.	In this Act, unless the context otherwise requires, -	
		(a)	"Act" means the Uttarakhand Private Universities Act, 2023,
		(b)	"Academic Council" means the Academic Council of the University,
		(c)	"Authorities" means Authorities of the University,
		(d)	"Board of Governors" means the Board of Governors of the University;
		(e)	"Board of Management" means the Board of Management of the University;
		(f)	"Bodies" means Bodies constituted by any Officer or the Authority of the University,
		(g)	"Capitation Fees" means any extra amount charged in cash or kind over and above the determined and displayed fee on the public domain;
		(h)	"College/Institution/School" means the college or institutions or school established and managed by the University.

	(i)	"Controller of Examination" means the Controller of Examination of the University.
	(j)	"Dean" means the Dean of a Faculty of the University.
	(k)	"Department" means a Department designated as such by the Ordinances or Regulations with reference to a subject or group of subjects;
	(l)	"Director" means the Head of an Institution, including a Centre, of the University;
	(m)	"Employee" means any person appointed by the University including teacher or other staff;
	(n)	"Evaluation Committee" means an Evaluation Committee constituted to evaluate the proposals received for the establishment of a Private Universities;
	(o)	"Faculty" means the faculty of the University consisting of some Departments.
	(p)	"Finance Committee" means the Finance Committee of the University;
	(q)	"Finance Officer/Finance Controller" means the Finance Officer/Finance Controller of the University;
	(r)	"High Power Committee" means a High Power Committee constituted to recommend the proposals for establishing private universities in the State of Uttarakhand, under this Act;
	(s)	"Higher Education" means study of a curriculum or course for the pursuit of knowledge beyond 10+2 level;
	(t)	"Hill Region" means such areas, blocks or districts defined by the State Government in its latest notifications, as Hill Region;
	(u)	"hostel" means a unit of residence for the students of the University or its constituent colleges or institutions maintained by the University in accordance with the provisions of this Act or the Statutes or Ordinances;
	(v)	"Main Campus" means the main campus of the private University situated in Uttarakhand State, in which the university headquarters with at least five educational departments are in the same place;
	(w)	"Off-campus Centre/Campus" means a Centre/Campus established, operated and maintained by the private university as its constituent unit outside the main campus within the jurisdiction of the Uttarakhand State with the prior approval of University Grants Commission and the State Government;

(x)	"Off shore Campus" means a campus established, operated and maintained by the private university as its constituent unit outside the country with only after obtaining due permission of the Government of India and also that of the Government of the host country.
(y)	"Officers of the University" means the officers of the University.
(z)	"Ordinances" means the Ordinances of the University made under the provisions of this Act;
(za)	"Permanent Resident" means such resident of the State, who has the domicile/permanent residence certificate as per the rules framed by the State Government from time to time.
(zb)	"Prescribed" means prescribed by the Statutes, Ordinances or Regulations made under this Act;
(zc)	"President" means the President of the University.
(zd)	"Principal" means the Principal of a Campus College of the University;
(ze)	"Pro-Vice-Chancellor" means the Pro-Vice-Chancellor of the University.
(zf)	"Registrar" means the Registrar of the University.
(zg)	"Regulations" means the Regulations of the University made under the provisions of this Act;
(zh)	"Regulatory Bodies" means the regulatory bodies established by the Central, State Governments from time to time such as University Grants Commission, All India Council of Technical Education (AICTE), National Council for Teachers Education (NCTE), Bar Council of India (BCI), National Medical Commission (NMC), Central Council of Indian Medicine (CCIM), Pharmacy Council of India (PCI), Indian Nursing Council (INC), Dental Council of India (DCI), Central Council for Homeopathy (CCH), Indian Council for Agricultural Research (ICAR), Council of Architecture (C Arch), Distance Education Board (DEB), Rehabilitation Council of India (RCI), National Council of Rural Institutes (NCRI), etc;
(zi)	"Schedule" means the Schedule appended to this Act;
(zj)	"Sponsoring Body" means,- <ul style="list-style-type: none"> Any Society 'not for profit' registered in Uttarakhand under the Societies Registration Act 1860, (Act no 21 of 1860) or any other corresponding law for the time being in force in the State; or

- Any Public Trust registered under the Indian Trusts Act, 1882 (Act No. 2 of 1882); or
- Any Company registered under the Companies Act, 1956 (Act No. 1 of 1956), and
- Any company registered under the Companies Act, 2013,

wishes to establish University under the provisions of this Act

(2k) "State" means the State of Uttarakhand;

(2l) "Statutes" means the Statutes of the University made under the provisions of this Act;

(2m) "Study Centre" means a center established and maintained or recognized by the University for the purpose of advising, counselling or for rendering any other assistance required by the students used in the context of distance education with the prior approval of University Grants Commission and the State Government;

(2n) "student" means any person enrolled in the University for any degree, diploma or other course, including research conducted by the University;

(2o) "teacher" means a Professor, Associate Professor, Assistant Professor Reader or any other person, appointed as per qualification prescribed by the Regulatory Body, required to impart education or to guide for research or to render guidance in any other form to the students studying in the University;

(2p) "University Grants Commission" means the University Grants Commission established under section 4 of the University Grants Commission Act, 1956;

(2q) "University" means a private University established or incorporated under the provision of this Act;

(2r) "Vice-Chancellor" means the Vice-Chancellor of the University; and

(2s) "Visitor" means the Visitor of the University.

CHAPTER II

Establishment of University

Condition for the establishment of the University

3. The Sponsoring Body, for the purposes of establishing and operating the private University under this Act, shall follow the guidelines and fulfill all the conditions as specified by the notification in this connection by State Government and Regulatory Bodies from time to time.

Submission of Proposal for Establishment of the University	4.	The sponsoring body desirous to establish a private University by a law of the State Legislature, shall make an application to the State Government, containing among other things an outline of the purpose and vision of the proposed University and the proposal and the Project Report in such manner containing such particulars along with such fee, as may be prescribed by the State Government, from time to time.
Evaluation and recommendation of proposals	5.	The Higher Education Department of the State Government, on receipt of the proposal and the project report for establishment of a University, shall constitute an Evaluation Committee for evaluation and a High Power Committee for recommendation, of the proposals, in a manner as prescribed.
Issuance of letter of intent and submission of compliance report by Sponsoring Body	6.	After the receipt of the report of the Committee constituted under section 5, if the State Government is satisfied that it is justified to establish the University, it may issue a 'Letter of Intent' to the Sponsoring Body.
Establishment of the University	7.	(1) The State Government, if satisfied that the Sponsoring Body has fulfilled the conditions for establishment of the University as mentioned in Section-3 and has complied with the terms and conditions of Letter of Intent, issued under the Section 6, it may, after getting the University incorporated as per the provisions of sub section (4) of Section-8 by a notification published in gazette, permit a Private University to be established and operate, with such name and place.
		(2) The University shall start functioning on) after getting the letter of authorization issued by the State Government for functioning of the University.
		(3) After establishment of the University, the name of the newly established Universities shall be mentioned in schedule 2 of this Act.
		(4) The land, building and other infrastructure pledged/acquired/constructed/created for the University shall not be utilized for any purpose, other than for which the same is acquired or constructed.
		(5) All the properties of the University shall remain vested in the University and no employee, officer or the member of any Authority of the University shall have any personal or proprietary rights on these properties.
		(6) The University shall not offer its programmes through franchising arrangement with other institutions/colleges or private coaching institutions even though the courses have to be conducted through distance mode.

- (7) The University after five years of its creation and after the development of main campus with prior approval of the State Government, may open another campus, off campus centers, off shore campuses and study centers.

Provided that the University before establishing another campus, off-campus center, off shore campus and study center outside the main campus, shall comply with the Regulation issued from time to time by the University Grants Commission/Regulatory Bodies.

CHAPTER - III

Incorporation of University and its Objectives

Incorporation of Universities

- 1) On the commencement of this Act the existing Private Universities enumerated in schedule I shall stand incorporated and established under this Act.
- (2) The President, the Vice-Chancellor, members of the Board of Governors, the Board of Management and the Academic Council, Registrar for the time being holding office as such in the University so established, shall constitute a body corporate by the name of the University.
- (3) The University shall have perpetual succession and a common seal, and shall sue and be sued by the said name.
- (4) The State Government may, from time to time, by enacting in State Legislative Assembly and by notification in the Official Gazette incorporate any new private university or modify, increase or alter the area of operation and function of any University, incorporated under this Act.

Objectives of the University

- 2) The objectives of the University shall be to ensure promotion and advancement of knowledge and skills by making arrangements for instruction, research and extension in such branches of learning as it may deem fit. University shall endeavor to provide to students, researchers and teachers the necessary atmosphere and facilities for the promotion of the following:-
- (a) Innovations in education, leading to restructuring of courses, new methods of teaching, training and learning including online learning, blended learning, continuing education and such other modes that paves the way for holistic and healthy development of personality;
- (b) Studies and Research in various disciplines;
- (c) Multidisciplinary and Interdisciplinary Studies and Research;

	(d)	Nations, integration, patriotism, secularism, social equity and inculcation of international understanding and ethics;
	(e)	To make learning more responsive to industrial and social needs and for holistic development associating the University closely with local, regional and national challenges; and
	(f)	Pursue any other objectives as may be approved by the Government.
Powers of the University:	10.	Subject to the guidelines and norms as prescribed from time to time by the Regulatory Bodies and the State Government the University shall have the following powers, -
	(a)	to provide provisions for instruction in such branches of learning as the University may, from time to time, determine and to make provisions for research and for the advancement and dissemination of knowledge and skills;
	(b)	to honour educational stalwarts and persons of academic eminence with designation of Professor Emeritus;
	(c)	to grant, subject to such conditions as the University may determine, diplomas or certificates, and confer degrees or other academic distinctions to persons on the basis of examinations evaluation or any other method of testing, and to withdraw any such diplomas, certificates, degrees or other academic distinctions for good and sufficient cause;
	(d)	to confer honorary degrees with prior approval of the Visitor;
	(e)	to institute as per norms of Regulatory Bodies and State Government Directorships, Professorships, Associate Professorships, Assistant Professorships, and other teaching or academic posts required by the University and to make appointments for the same;
	(f)	to create administrative, clerical and other posts and to make appointments thereto;
	(g)	to disseminate learning through various suitable modes such as seminars, conferences, workshops, educational programs, community development program, publication, training programs etc.;
	(h)	to appoint or engage permanently or for a specified period persons of eminence from Industry, Academic or Research fields;
	(i)	to co-operate, collaborate or associate with any other University or Institution or Industrial and Social Organization in India or abroad in such manner and for such purpose as the University may determine;

	(j)	to establish and maintain such schools, faculties, departments, centers, specialized laboratories and other units for research and education as are in the opinion of the University, necessary for the furtherance of its objectives;
	(k)	to institute and award fellowships, scholarships, studentships, medals and prizes;
	(l)	to create a 'Corpus' fund for sustained and self-sufficient growth of the university;
	(m)	to establish, maintain and manage the hostels for students and residences of faculty and staff;
	(n)	to make provisions for functioning of University in accordance with the administrative and financial rules and procedures laid down by the University;
	(o)	to make provisions for research and consultancy;
	(p)	to determine standards for admissions into the University, which may include examination, evaluation or any other method of testing to ensure quality in accordance with the norms of State Government and other Regulatory Bodies;
	(q)	to determine, demand and receive fee and other charges;
	(r)	to lay down conditions of service of all categories of employees including their code of conduct;
	(s)	to make special arrangements in respect of women and other disadvantaged students as the University may consider desirable;
	(t)	to regulate and enforce discipline among the students and the employees, and to take such decisions in this regard as may be deemed necessary by the University;
	(u)	to make arrangements for promoting the health and general welfare of the employees of the University;
	(v)	to condemn or dispose off movable properties with the prior permission of the Sponsoring Body and as per provision of the Statutes, Ordinances and Regulations;
	(w)	To receive donations and to acquire, hold and manage any property, movable or immovable for the welfare of the University;

		(x)	to raise, collect, subscribe and borrow money for the purpose of University with approval of the Board of Governors and the Sponsoring Body, whether on the security or the property of the University;
		(y)	to ensure that no immovable property shall be disposed off or rights or title therein parted with or any liability created thereon, by any of the officers or authorities of the University, without prior approval of the State Government;
		(z)	to appoint either on contract or otherwise, visiting professors, eminent professors, consultants, fellows, scholars, artists, course directors and such other persons who may contribute to the advancement of the objectives of the University;
		(za)	to make donations or grants or providing assistance to institutions, social institutions and charitable institutions having similar objectives,
		(zb)	to organize and to undertake extramural studies and extension service;
		(zc)	to organize and conduct orientation courses, refresher courses, workshops, seminars and other programs for teachers, staff and students,
		(zd)	to enter into, carry out, amend or cancel contracts,
		(ze)	to recognize examinations or period of studies (whether in full or part) of other Universities, institutions or other institutions of higher learning as equivalent to examinations or period of study of the University and to withdraw such recognition at any time;
		(zf)	to provide education in distance mode with the approval of the University Grants Commission, Regulatory Body and the State Government, and
		(zg)	to do all such other acts or things as may be necessary, incidental or conducive for smooth functioning and to attainment of all or any of the objectives of the University
Admission and Academic Standards	11.	(1)	Admissions in all academic programmes, conducted by the University, shall be made by the admission committee as per the norms determined in accordance with the provisions of the Act, the Statutes and Ordinances made there under;
		(2)	The University shall ensure that the academic standards of the courses offered by the University are in accordance with the guidelines of the Regulatory Bodies;

	(7) The teacher-student ratio shall be in accordance with the guidelines of the Regulatory Bodies.
<i>University open to all Classes and Creeds</i>	<p>12. The University shall be open to persons of all sex and of whatever race, creed, caste or class, and it shall not be lawful for the University to adopt and to impose on any person any test whatsoever of his religious belief or profession in order to entitle him to be admitted therein as an officer, a teacher, staff member, student, or to hold any office therein or to graduate there at:</p> <p>Provided that nothing in this section shall be deemed to prevent the University from making special provisions for admission into various programs offered by the University for the permanent residents of the State of Uttarakhand.</p>
<i>Provisions for Permanent Residents of the State of Uttarakhand</i>	<p>13. (1) Notwithstanding anything contained in this Act for admission in various courses conducted by the private University minimum 25 (Twenty-five) percent or percentage of seats declared in the affidavit shall be reserved for the permanent resident of the State of Uttarakhand</p> <p>Provided that if some seats, reserved for the permanent residents of the Uttarakhand, remain vacant, the University shall fix and publish the last date to fill these seats. If the permanent residents of Uttarakhand are not available after the last date fixed then the University may fill these seats by other eligible candidates:</p> <p>Provided further that the reservation policy of the State Government shall be applicable for admission for seat reserved for permanent resident of Uttarakhand.</p>
	(2) In tuition fee of various courses conducted by the private university, at least 25 (Twenty Five) percent rebate or percentage declared in affidavit shall be given to the permanent residents of Uttarakhand who are admitted under sub-section (1) above
	(3) Qualified permanent residents of Uttarakhand shall be appointed against all post/vacancies of Group C and D
<i>No Power to Affiliate any Institution</i>	14. The University may have its own Constituent Institutions/Colleges, Regional Centers, Study Center and Training & Research Centers but the University shall have no power to affiliate any College/Institution etc

CHAPTER IV

Officers of the University

<i>Officers of the University</i>	15. The following shall be the officers of the University, namely
	(a) The Visitor,
	(b) The President

		(c) The Vice-Chancellor;
		(d) The Pro-Vice-Chancellor;
		(e) The Dean, Principal/Chief of
		(f) The Registrar;
		(g) The Finance Officer;
		(h) The Controller of Examinations; and
		(i) such other officers as may be defined and declared by the Statutes to be the officers of the University.
The Visitor	16.	(1) The Governor of Uttarakhand shall be the Visitor of the University.
		(2) The Visitor when present shall preside over the convocation of the University.
		(3) Every proposal for the conferment of an honorary degree shall be subject to the approval of the Visitor.
		(4) The Visitor shall have the following powers, namely:-
		(a) To call for any paper or information relating to the affairs of the University;
		(b) On the basis of the information received by the Visitor, if he is satisfied that any order, minutes or decision taken by any authority of the University is not in conformity with the Act, Statutes, Rules, Regulation or Ordinance he may issue such directions as he may deem fit in the interest of the University and the directions so issued shall be complied with by all concerned office bearers.
The President	17.	(1) The President shall be appointed by the Sponsoring Body for a period of 05 (five) years by following such procedure and on such emoluments, terms and conditions as may be prescribed.
		Provided that he may be re-appointed by the Sponsoring Body
		(2) The President shall be the Head of the University. He shall be ex-officio Chairman of the Board of Governor and shall preside over the convocation of the University in the absence of the Visitor.
		(3) If in the opinion of the President, it is necessary to take immediate action on any matter for which powers are conferred on any authority under this Act, he may take such action as he deems necessary.
		(4) If, at any time, upon representation made or otherwise, and after making such inquiry, as may be deemed necessary, the situation so warrants that the continuance of the President in his post is not in the interest of the University, the Sponsoring Body, after following the procedure as prescribed by the statute, may ask the President to demit his office.

		<p>Provided that before taking an action under this sub-section, the President shall be given an opportunity of being heard.</p> <p>(5) The President shall have the following powers, namely:-</p> <p>(a) he shall be appellate authority for hearing the appeals against the decisions of the Board of Management as disciplinary (appointing) authority of the teachers or equivalent;</p> <p>(b) to call for any information or record of the University;</p> <p>(c) to appoint the Vice-Chancellor under sub-section (1) of section 18 of this Act;</p> <p>(d) to remove the Vice-Chancellor under sub-section (6) of Section 18 of this Act; and</p> <p>(e) such other powers as may be prescribed by the Statutes.</p>
The Vice-Chancellor	18.	<p>(1) The Vice Chancellor shall be whole time salaried officer of the University who shall be responsible for over-all functions of the University and shall function through authorities and officers of the University.</p> <p>(2) The Vice-Chancellor shall be an eminent academician with strong administrative acumen. He shall fulfill the qualification and experience prescribed in the Regulations of University Grants Commission or other Regulatory Bodies, from time to time.</p> <p>(3) The Vice Chancellor shall be appointed, subject to fulfilling the qualification as per sub-section (2), and on such terms and conditions as may be prescribed by the Statutes, for a period of three years by the President, from a panel of three persons recommended by the Search-cum-Selection Committee constituted under sub-section (4).</p> <p>Provided that the Vice-Chancellor shall be eligible for reappointment subject to the approval of the Board of Governors.</p> <p>Provided further that no person shall be appointed or hold the post of the Vice-Chancellor after attaining the age as determined by the Regulatory body.</p> <p>(4) The Committee referred in sub-section (3) shall consist of the following persons, namely:-</p>

		(a)	One member nominated by the Visitor,
		(b)	One member nominated by the President,
		(b)	One member nominated by UGC;
		(d)	Principal Secretary Secretary, Department of Higher Education, Government of Uttarakhand,
		(e)	Two members nominated by the Board of Governors-one of whom shall be nominated by the Board of Governors as convener of the committee.
		(5)	<p>The Committee constituted under sub-section (4) shall on the basis of merit, prepare a panel of names of three persons suitable to hold the office of the Vice-Chancellor and forward the same to the President along with a concise statement showing the academic qualifications and other distinctions of each person.</p> <p>Provided that if the President is not satisfied/ agreed with the panel recommended by the search cum selection committee, he shall with reasons of disagreement call for a fresh panel only one more time.</p>
		(6)	<p>If, at any time, upon representation made or otherwise, and after making such enquiry, as may be deemed necessary, the situation so warrants that continuance of the Vice-Chancellor is not in the interest of the University the President, by an order in writing stating the reasons thereof, may ask the Vice-Chancellor to demit his office from such date as may be specified in the order.</p> <p>Provided that before taking an action under this sub-section, the Vice-Chancellor shall be given an opportunity of being heard.</p>
Powers and Duties of the Vice-Chancellor	19.	(1)	<p>The Vice-Chancellor, shall be principal academic and executive head of the University who shall exercise general supervision and control over affairs of the University and its constituent Colleges Institutions/Schools. He shall,</p>
		(a)	provide over the convocation of the University in the absence of the Visitor and the President;
		(b)	implement the decisions of the President and authorities of the University;
		(c)	be ex-officio Chairman of the Board of Management, the Academic Council and the Finance Committee;
		(d)	ensure the observance of the provisions of Act, Statutes, Ordinances, Regulation and Rules,

		(e) be responsible for the proper administration, co-ordination, utilization of funds, timely holding the examination and declaration of the results and maintenance of discipline in the University; and
		(f) have the right to speak in and otherwise take part in the meeting of any other authority or body of the University but shall not by virtue of this sub section be entitled to vote
		(2) If in the opinion of the Vice-Chancellor, it is necessary to take immediate action on any matter for which powers are conferred on any authority, under his control, under this Act, he may take such action as he deems necessary and shall at the earliest opportunity thereafter report his action to such officer or authority as it would have in the ordinary course dealt with the matter. Provided that if in the opinion of the concerned officer or authority such action should not have been taken by the Vice-Chancellor, then the person aggrieved by the decision shall have the right to appeal, within a period of two months from the date of communication or knowledge of such decision, before the President, whose decision thereon shall be final.
		(3) The Vice-Chancellor shall exercise such other powers and perform such duties as may be prescribed by the Statutes or delegated by the Board of Governors or the President.
The Pro-Vice-Chancellor	20.	(1) The Pro-Vice Chancellor shall be appointed by the President on the recommendation of the Vice-Chancellor in such manner as prescribed by the Statute, and he shall exercise such powers and perform such duties as may be prescribed by the Statutes or provided in the Ordinances and regulations (2) The Pro-Vice Chancellor appointed under sub-section (1) shall discharge his duties in addition to his duties as a Professor (3) The Pro-Vice-Chancellor shall assist the Vice-Chancellor in discharging day-to-day duties as and when required by the Vice-Chancellor
Dean/ Principal/ Director	21.	The Dean/Principal/Director of each faculty/constituent college institution/school of the University shall be appointed in such manner and shall exercise such powers and perform such duties as may be prescribed by the Statutes.
The Registrar	22.	(1) The Registrar shall be a whole-time salaried Officer of the University and shall be appointed by the President in such manner and on such terms and conditions as may be prescribed by the Statutes.

		(2) The Registrar by virtue of his office shall be the member secretary in the Board of Management and the Academic Council and Secretary for the selection committee of the teachers and shall be a member of Finance Committee and other committees or bodies, as may be prescribed by Statutes and Ordinances.
		(3) The Registrar shall be custodian of records, property and common seal of the University and he shall have the power to authenticate records on behalf of the University.
		(4) The Registrar shall have the power to enter into contract, sign documents on behalf of the University.
		(5) The Registrar shall be bound to place before the authorities all such information as may be necessary for transaction of their business. He shall exercise such other powers and perform such other duties as may be prescribed by the Statute, Ordinances or Regulations or as may be delegated to him by the Vice-Chancellor and other Authorities from time to time.
The Finance Officer	23.	(1) The Finance Officer shall be appointed in such manner and shall exercise such powers and perform such duties as may be prescribed.
		(2) The Finance Officer shall, be the <i>ex-officio</i> secretary of the Finance Committee.
The Controller of Examinations	24.	(1) The Controller of Examinations shall be appointed in such manner and shall exercise such powers and perform such duties as may be prescribed by the Statutes, Ordinance and Regulations.
		(2) The Controller of Examinations shall be the member secretary of the Board of Examinations.
Other officers	25.	The procedure of appointment, terms and conditions of service, powers and duties of other officers of the University shall be as prescribed by Statutes.

CHAPTER V Authorities of the University

Authorities of the University	26.	The following shall be Authorities of the University, namely -
	(a)	The Board of Governors,
	(b)	The Board of Management,
	(c)	The Academic Council,

		(d) The Board of Examinations,
		(e) The Board of Studies,
		(f) The Planning Board,
		(g) The Finance Committee, and
		(h) Such other authorities as may be prescribed by the Statutes to be the authorities of the University.

The Board of Governors

- 27 (1) The Board of Governors shall be the Principal Governing Authority of the University who shall control its functioning, by using all such powers as prescribed by Statutes, Ordinances or Regulations.
- (2) The Board of Governors of the University shall consist of following :-
- (a) The President / Chairman,
 - (b) The Vice-Chancellor - Member Secretary,
 - (c) Two distinguished academicians nominated by the Visitor,
 - (d) Two distinguished academicians nominated by the State Government;
 - (e) The Principal Secretary/Secretary, Department of Higher Education, Government of Uttarakhand or a person nominated by him not below the rank of Additional Secretary,
 - (f) Three distinguished persons nominated by the President from the fields of Administration, Corporate Management / IT etc., and
 - (g) Five distinguished persons nominated by the Spreading Body, out of whom at least one should be an academician.
- (3) The Board of Governors shall meet at least twice in a year or such date and place as the President may fix.

Provided that the President may whenever he thinks fit or shall upon a requisition in writing signed by not less than one fourth of the total members convene a special meeting of the Board of Governors.

- (4) The Board of Governors shall have the following powers namely, -

		(d) The Principal Secretary, Secretary, Department of Higher Education, Government of Uttarakhand or person nominated by him not below the rank of Additional Secretary,
		(e) Maximum three Deans/Principals/Directors on the basis of rotation, nominated by the President,
		(f) Two Professors, on recommendation of Vice-Chancellor, nominated by the President on the basis of seniority and rotation
		(g) The Finance Officer, and
		(h) The Registrar Member Secretary
	(2)	The meetings of the Board of Management shall be held in such manner as may be prescribed
	(3)	The Board of Management shall exercise such powers and perform such functions as prescribed by statutes.
<i>The Academic Council</i>	29	(1) The Academic Council shall be the principal academic authority of the University and shall subject to the provisions of the Statutes, the Ordinances and Regulations, determine, co-ordinate and exercise general supervision over the academic policies of the University
	(2)	The constitution of the Academic Council, the term of office of its members and its powers and functions shall be such as may be prescribed by the Statutes.
<i>The Board of Examinations</i>	30	The constitution, powers and functions of the Board of Examinations shall be as prescribed by the Statutes and Ordinances or Regulations
<i>The Boards of Studies</i>	31	The constitution, powers and function of the Boards of Studies shall be as prescribed by the Statutes
<i>The Planning Board</i>	32	(1) The Planning Board shall be the principal Planning Body of the University which shall ensure that the infrastructure and academic support system meets the norms of the University Grants Commission and other Regulatory Bodies.
	(2)	The constitution of the Planning Board, term of office of its members and its powers and functions shall be such as may be prescribed by the Statutes
<i>The Finance Committee</i>	33	(1) The Finance Committee shall be Principal Financial Authority, for policy making and management of financial matters of the University

	(2)	The constitution, powers and functions of the Finance Committee shall be such, as may be prescribed by the Statutes.
<i>Other authorities of University</i>	34.	The constitution, powers and functions of other authorities declared by the Statutes, of the University, shall be such as may be prescribed.
<i>Disqualification of the Members of an Authority or Body</i>	35.	(1) A person shall be disqualified for being a member of any authorities or bodies of the University, if he - (a) is of unsound mind and stands so declared by a competent medical board, (b) is an undischarged insolvent, (c) has been convicted of any offence involving moral turpitude, (d) has been punished for indulging in or promoting unfair practice in the conduct of any examination, in any form, anywhere; (e) has any motive of profit from University except salary or any other authorized emoluments, (f) applies funds of the University for his personal use.

CHAPTER VI Statutes, Ordinances and Regulations

<i>Powers to make Statutes</i>	36.	(1) The First and amended Statutes of the Universities incorporated and established under this Act shall be made by the Board of Governors on recommendation of the Board of Management and shall be submitted before the State Government for its approval. (2) Within 93 (three) months from the date of receipt of the Statutes the Government shall consider and approve or return the same to the University for modification with its suggestions. (3) Subject to the provisions of this Act, the Statutes may provide for all or any of the following matters, namely, - (a) constitution, powers and functions of the Authorities of the University or as may be constituted from time to time,
--------------------------------	-----	--

		(b)	appointment and continuance of all or of the members of the Authorities filling of vacancies of the members of the Authorities and all other matters relating to authorities for which it may be necessary to make provisions,
		(c)	appointment, powers and duties of the officers of the University and their emoluments,
		(d)	appointment of teachers, other academic, administrative and non academic employees and their emoluments,
		(e)	appointment of teachers and other academic and administrative staff working in the University or institution for specific period for undertaking a joint project,
		(f)	conditions of service of employees including provisions for retirement benefits, insurance and provident fund, the manner of termination of service and disciplinary actions,
		(g)	principles governing seniority of service of employees,
		(h)	procedure for resolving disputes between university and its officers, teachers, employees or students,
		(i)	institution and condition for award of fellowships, scholarships, studentships, medals and prizes,
		(j)	procedure for filing appeal by any employee or student against the action of any officer or authority of the University and its disposal;
		(k)	conferment of honorary degrees,
		(l)	withdrawal or cancellation of degree, diploma, certificate and other academic distinctions,
		(m)	operation of the permanent endowment fund, the general fund and the development fund,
		(n)	establishment, merger and abolition of Departments,
		(o)	maintenance of discipline among the students and employees;
		(p)	Creation and abolition of posts,
		(q)	Process of dissolution winding up of the University, and
		(r)	all other matters as per this Act or as may be prescribed

		(4)	The Board of Management shall not make, amend or repeal any Statute affecting the powers or constitution of any authority of the University until such authority has been given an opportunity of expressing an opinion in writing on the proposed changes and any opinion so expressed shall be considered by the Board of Management
Power to make Ordinances	37	(1)	Subject to the provisions of this Act and the Statutes, the Ordinances shall be made by the Board of Management which may provide for all or any of the following matters, namely, -
		(a)	the admission of students to the University and their enrolment as such,
		(b)	the determination of courses of study to be laid down for all degrees, diplomas and certificates of the University,
		(c)	the medium of education and examination,
		(d)	the award of degree, diploma, certificate and other academic distinction and determination of eligibility and measures to be taken for awarding or obtaining the same,
		(e)	the determination of tuition fee for various programs and chargeable fee for examinations, degrees, diplomas and certificates of the University,
		(f)	the conditions for the award of fellowships, scholarships, studentships, medals and prizes,
		(g)	the conduct of examinations including the term of office and the manner of appointment and duties of the Examination Committee, examiners, invigilators, tabulators and moderators,
		(h)	the conditions of residence of the students of the University,
		(i)	special arrangements, if any, to be made for the residence, discipline and teaching of girl students and to prescribe special courses of studies for them under the University;
		(j)	the appointment and emoluments of employees other than those for whom provision has been made in the Statutes,
		(k)	the establishment of Centre of Studies, Board of Studies, Interdisciplinary Studies, Special Centers, Specialized Laboratories and other Committees;

		(i) the manner of co-operation and collaboration with other Universities and Institutions including professional bodies or associations,
		(ii) the creation, composition and functions of any other body committee which is considered necessary for improving the academic standard of the University
		(iii) the remuneration to be paid to the examiners moderators, invigilators and tabulators, and
		(iv) other matters as prescribed by the Act or Statutes
Power to make Regulations	38	For academic administrative and other activities of the University the authorities of the University may make Regulations not inconsistent with the provisions of this Act, Statutes and Ordinances
Publication of Statutes, Ordinances and Regulation	39	Every Statute, Ordinance and Regulation made under this Act shall be published by the University and shall also uploaded in its website and the public domain
Convocation	40	The Convocations of the University, for conferring degree diplomas or for any other purpose may be held regularly in the manner as may be prescribed by the Statutes Ordinances and Regulations
Accreditation of University	41	Within a period of five years from commencement of programmes the University shall obtain NAAC and other such accreditations as may be prescribed by the State Government from time to time. It shall also obtain certification accreditation from such other Regulating Bodies which are connected with the courses conducted by the University. It shall inform the State Government about the grade obtained by the University. The University shall ensure renewal of such accreditation from time to time

CHAPTER – VII

Funds and Account of the University

Permanent Endowment Fund	42	(1) The Sponsoring Body shall establish a Permanent Endowment Fund of at least of Rupees 05 (Five) crore for plane areas and Rupees 3 (Three) crore for hill areas in the form of a Bank Guarantee of a Nationalized Bank Pledged in the name of State Government for a period of 05 (five) years and it shall be renewed after every five years and after every five year the said Bank Guarantee shall be increased by 25 percent
---------------------------------	----	---

		(2) The Endowment Fund shall be used as security deposit to ensure that the University complies with the provisions of this Act and functions as per the provisions of this Act, the Statutes, the Ordinances and the Regulations made there under. The State Government shall have the powers to forfeit, a part or whole of the Endowment Fund, in case the University or the Sponsoring Body contravenes the provisions of this Act, the Statutes, the Ordinances or the Regulations made there under.
		(3) The University may utilize the income from Endowment Fund for the development of infrastructures of the University or for meeting the recurring expenditure of the University.
General Funds	43.	The University shall establish a General Fund to which the following amount shall be credited, namely, -
		(a) all fees which may be charged by the University;
		(b) all sums received from any other sources;
		(c) all contributions made by the sponsoring body and
		(d) all contributions made in this behalf by any other person, institutions or bodies which are not prohibited by any law for the time being in force.
	(2)	The money credited to the general fund shall be applied for development of the University and to meet a) the expenses for its smooth functioning.
Development Funds	44.	(1) The University shall also establish a development fund to which the following moneys shall be credited, namely, -
		(a) development fees, which may be charged from students;
		(b) all sums received from other sources for the purpose of the development of the University;
		(c) all contributions made by the Sponsoring Body;
		(d) contributions made in this behalf by any other person or bodies which are not prohibited by any law for the time being in force; and
		(e) all incomes received from the permanent endowment fund.
	(2)	The money credited to the development fund from time to time shall be utilized for the development of the University.
Maintenance of Funds	45.	All funds established under this Act shall be subject to general supervision and control of the Board of Governors and shall be regulated and maintained in such manner as may be prescribed.

Annual Report	46.	(1)	The Annual Report of the University shall be prepared under the direction of the Board of Management and shall be submitted to the Board of Governors on such date as may be prescribed. The Board of Governors in its annual meeting shall consider and approve the Annual Report.
		(2)	Approved Annual Report shall be submitted to the Visitor and State Government before 31 st December each year.
Annual Account and Audit	47.	(1)	The annual accounts and balance sheet of the University shall be prepared under the direction of the Board of Management and at least once every year and at intervals of not more than fifteen months, be audited by an experienced and qualified firm of Chartered Accountants of repute.
		(2)	A copy of the annual accounts and the balance sheet together with the audit report and the observations of the Board of Management shall be submitted to the President and the Board of Governors for consideration in the Annual Meeting.
		(3)	The Board of Governors in its annual meeting shall consider and approve the annual accounts and audit report. Observations on annual accounts, if any, shall be brought to the notice of the Board of Management. The Board of Management after reviewing the observations, if any, shall submit the audit report before the President for approval.
		(4)	A copy of the annual account and balance sheet duly approved by the Board of Governors shall be sent to the Visitor and the State Government before 31 st December each year for information and uploading it in the website of the concern Department.
		(5)	The directions of the State Government on the subject arising out of the account and the audit report of the University shall be binding on the University.
The University shall be self-financed	48.		<p>The University shall not be entitled for any grants, aid or any financial assistance from the State Government or any other body or Corporation owned and controlled by the State Government.</p> <p>Provided that the University shall be entitled to receive any such grant which may be granted under any special scheme of the State/Central Government or any body or corporate, owned or controlled by the State/Central Government subject to the condition of such a grant.</p>

CHAPTER VIII

Role of the State

Government and Regulatory Bodies

University to follow rules, regulations, norms, etc. of regulatory bodies

49.

Notwithstanding anything contained in this Act, the University shall be bound to comply with all the rules, regulations, norms, etc. of the regulating bodies of Government of India and provide all such facilities and assistance to such bodies as are required by them to discharge their duties and carry out their functions.

Power of State Government to call for information and records

50.

It shall be the duty of the University or any authority or officer of the University to furnish such information or records relating to the administration or finances and other affairs or activities etc. of the University as the State Government may call for.

Role of the Government and Regulatory Bodies

51.

(1) The University, as an autonomous body shall function independently within broad policy frame work of the State Government and in accordance with the Regulations and Guidelines of Regulatory Bodies. The role of the State Government and the Regulatory Bodies shall be to ensure that the functioning of the University is as per the provisions of the Act, Statutes, Ordinances and Regulations and the State Government and Regulatory Bodies may interfere for a constructive resolve in the greater academic interests including periodic inspection.

(2) The State Government may issue such directions from time to time to the University on policy matters not inconsistent with the provisions of this Act as it may deem necessary. Such directions shall be complied by the University, failing which the State Government may take a reasonable action against the University.

(3) On identification of gross mismanagement, mal-practice, fraud or misappropriation or serious misuses of funds, failure in the accomplishment of the objectives of the University or non-compliance of the provision of Letter of Intent and any provision of this Act, the State Government shall issue notice requiring the University to show cause within two months.

(4) Upon receipt of the reply from the University or the notice issued under sub-section (3) if the Government is satisfied that the University has violated any provisions of this Act or Statutes, it shall conduct such inquiry as it may deem fit.

(5) If, on receipt of the report of the enquiry conducted under sub-section (4), the State Government is satisfied that the University has violated any provision of this Act or Statute, then it may take appropriate action, including imposing the penalty on the University, recommend to the regulatory Bodies to de-accredit the University or winding up of the University.

		(6)	Without prior approval of the State Government no immovable property of the University shall be disposed of, sold or transferred by any of the officers or authorities of the University.
Fee	52.	(1)	The fee structure for all purpose shall be determined by the Board of Management on recommendations of a Fee Fixation Committee, constituted by the Board of Governors. The Fee Fixation Committee shall consist of members drawn from Board of Management, Academic Council, as well as external experts related to the programs and accounts. A senior member of the Board of Management shall be Head of the Fee Fixation Committee.
		(2)	Fees determined by the Board of Management shall be valid for 03 (three) consecutive academic years. All fees and charges determined by University shall be transparently and fairly disclosed along with the basis of fee fixation process. There shall be no increases in the tuition fees to be charged from an enrolled student during the period of completion of any course.
		(3)	The University shall not charge any fee, or any form of fee (capitation fee etc.) from its students over and above the fee fixed by the Fee Fixation Committee or by the Regulatory Bodies and there shall be no profiteering of education.
		(4)	The level of fees charge for the courses offered, shall have a reasonable relation to the cost of running the course (infrastructure, quality of teaching & research and other facilities). The Admission process and fee structure shall be published in the prospectus and uploaded on the website of the University before starting the admission in any course & session.
		(5)	The University shall preserve the complete proceedings and records of fee determination process and a copy shall be sent to the State Government for information, and for further consideration, if required.
		(6)	In the event of any written complaint, related to wrongly in fixation of fee, demand of fee or money in excess of fee fixed and displayed in public domain, lodged before the Board of Governors by any student enrolled in a course, the Board of Governors shall settle the matter itself or through the Student Grievance Redressal Committee constituted as per norms of University Grants Commission regulation.
		(7)	Any student aggrieved by the decision of the Board of Governors or the Student Grievance Redressal Committee may refer the case, along with supporting documents to the State Government, within two months of the decision of the University.

<i>Provision of Penalties</i>	(8) The State Government shall examine and decide the matter and its decision shall be final.
	(1) Whoever contravenes the provisions of this Act or the rules made there under for any examinations related matters or in matters relating to the admissions and award of degree or in issuing mark sheets or fee related matter or matter related to appointment of Faculty shall on conviction be punishable with fine of such amount as may be notified by the State Government from time to time. Provided that, where the University is also involved in committing the offence the authorization letter issued by the Government under this Act, to operate the University shall be withdrawn. (2) No court lower than the court of a Magistrate of the first class shall try an offence punishable under this Act, nor shall cognizance of any such offence be taken except on a complaint made by the Principal Secretary/ Secretary, Department of Higher Education Government of Uttarakhand or any other person authorized, in writing by him, by general or special order in that behalf.
	(3) Penalty under this Section may be imposed without prejudice to the penalty specified in any other Act.

CHAPTER IX

Dissolution/Winding Up of University

<i>Dissolution Winding up of University</i>	(1) If the Sponsoring Body proposes to dissolve, the University it shall give at least one year's prior notice in writing to the State Government.
	(2) On receipt of notice referred to in sub-section (1) the State Government shall make such arrangements in such manner as may be prescribed for administration of the University from the date of dissolution of the University and until the last batch of students in regular program of the University complete their program/studies.
	(3) If the State Government decides to wind up the University in pursuance to provisions of sub-section (5) of section 51, it shall initiate the process of winding up of the University in accordance with the Statutes made in this regard.

Provided that the process of winding up of University shall not be initiated without giving a reasonable opportunity of being heard to the Sponsoring Body

Expenditure of the University during Dissolution Winding up

(4) On the completion of the process of dissolution or winding up of the University under sub-sections (1) and (3) the State Government shall, by a notification in the Official Gazette, issue an order for dissolving or winding up of the University and from the date of publication of such notification, the University shall stand dissolved wound up and from such date all the remaining assets and liabilities of the University shall vest in the sponsoring body

(5) Every notification issued under sub-section 4 shall be placed before the State Legislature Assembly

(1) Once the decision regarding dissolution or winding up of the University is taken by the State Government, the expenditure for administration of the University during the process of dissolution winding up shall be met out from the permanent endowment fund the general fund or the development fund.

(2) If the funds referred in sub-section (1) are not sufficient to meet the expenditure and the liabilities of the University such expenditure and liabilities may be met out by the State Government by disposing off the properties and assets of the University

CHAPTER X

Miscellaneous and Transitory Provisions

Duties of Teachers

56. Every teacher of a University shall carry out the work related to teaching, research, examination or other work assigned to him by the University from time to time

Obligation to perform Examination work

57. Any person who is entrusted with the examination work relating to paper setting, invigilation supervision, evaluation, conduct of practical examination, tabulation and preparation of marks sheets and all such activities shall discharge his duties prudently and with utmost integrity

Returns and information	58	It shall be the duty of the University or any authority or officers of the University to furnish such information or records relating to the administration or finances and other affairs or activities etc. of the University as the State Government may call for
Conditions of service of employees etc.	59.	(1) Every employee of the University shall be appointed under a written contract, a copy of which shall be kept by the University and a copy of which shall be furnished to the employee concerned.
	(2)	Disciplinary action against the employees shall be taken under procedure prescribed in the relevant Statutes
	(3)	Any dispute arising between the University and any of the regular appointed employees shall be referred to the Vice-Chancellor. The Vice-Chancellor shall decide the dispute within 03 (three) months from the date of its reference after giving an opportunity of hearing to the employee.
	(4)	Any dispute in respect of any employee engaged temporarily or on ad-hoc or part time or casual basis shall be heard and decided by the Vice-Chancellor
	(5)	The employee aggrieved by the order of the Vice-Chancellor within a period of two months from the date of communication or knowledge of such order shall have the right to appeal before the President whose decision shall be final.
	(6)	Notwithstanding anything contained in this Act, the employees of the University shall not be deemed as Public Servant and would always remain as under the private employment of the University for the purpose of this Act or otherwise.
Right to appeal	60	Every employee or student of the University or of a College or Institution maintained by the University, notwithstanding anything contained in this Act, shall have a right to appeal, within such time as may be prescribed by the Statutes, to the Board of Governors against the decision of any officer or authority of the University, as the case may be, and thereupon the Board of Governors may confirm, modify or reverse the decision appealed against.

<i>The Grievance Redressal Committee</i>	61	<p>(1) There shall be a Grievance Redressal Committee in each University to deal with the grievances of teaching and non-teaching staff as well as students belonging to its departments to hear and redress them as far as may be practicable within three months. The Committee shall make periodical Reports to the Board of Management on the grievances dealt with by it.</p> <p>(2) The composition of the Grievance Redressal Committee, its powers, functions and the procedure to be followed by it in dealing with the grievances put up before it shall be as prescribed by the Statutes or regulations of Regulatory Bodies.</p>
<i>Provident fund and pension</i>	62	The University shall constitute for the benefit of its employees such provident fund or pension fund or welfare schemes or provide such insurance schemes as it may deem fit in such manner and subject to such conditions as may be prescribed by the Statutes.
<i>Disputes as to constitution of authorities and bodies</i>	63	If any question arises as to whether any person has been duly nominated or appointed as, or is entitled to be, a member of any authority or other body of the University, the matter shall be referred to the President whose decision thereon shall be final.
<i>Filling of casual vacancies</i>	64	A casual vacancy among the members (other than ex-officio members) of any authority or other body of the University shall be filled, as soon as may be, by the person or body who appoints, select or co-opts the member whose place has become vacant, and the person appointed, selected or co-opted to a casual vacancy shall be a member of such authority or body for the residue of the term for which the person whose place he fills would have been a member.
<i>Proceedings of authorities and bodies not to be invalidate due to vacancies</i>	65	No act or proceedings of authority or body of the University shall be invalid merely by reason of any vacancy or defect in constitution of the Authority or Body.
<i>Protection of action taken in good faith</i>	66	No suit or other legal proceedings shall lie against any officers or other employee of the University for anything which is done in good faith or intended to be done in pursuance of any of the provisions of this Act, the Statutes or the Ordinances and the Regulations.

Mode of proof of University records	67	A copy of any receipt, application, notice, order, proceeding, resolution of any authority or committee of the University or other documents or entry in the register which are in possession of the University, if certified by the Registrar, shall be received as prima facie evidence of the such receipt, applications, notice, order, proceeding/resolution, documents or the existence of entry in the register and shall be admitted as evidence of the matters and transactions therein recorded where the original thereof would, if produced have been admissible in evidence.
Powers of the Government to make rules	68	The Government may, by notification, make rules to carry out all or any of the purposes of this Act.
Power to remove difficulties	69	<p>(1) If any difficulty arises in giving effect to the provisions of this Act, the State Government may, by order published in the Official Gazette, make such provisions, not inconsistent with the provisions of this Act, as appear to it to be necessary or expedient for removing the difficulty.</p> <p>Provided that no such order shall be made after expiry of three years from the date of commencement of this Act.</p> <p>(2) Every order made under sub-section (1) shall be laid before the State Assembly as soon as after it is made.</p>
Disputes to be disposed in a Court in Uttarakhand	70	All disputes arising as a result of the provisions made in the Act and the Statutes, Ordinances and Regulations made there under shall be disposed of by a competent court of law in the State of Uttarakhand.
Overriding effect	71	In respect of Private Universities the provisions of this Act and the Statutes, Ordinances and Regulations made there under shall have overriding effect notwithstanding anything to the contrary contained in any other law, for time being in force, made by the State Legislature.
Repeal and saving	72	<p>(1) With commencement of this Act, all the Acts enumerated in column 2 of the Schedule I of this Act shall stand repealed.</p> <p>(2) Notwithstanding the repeal of the Acts enumerated in the Schedule mentioned in sub-section (1), all the decisions made, acts performed, rights and liabilities created and exhausted by the Universities established under such repealed Acts shall be deemed to be valid under this Act.</p>

		(V) The Statutes, Ordinances, Rules and Regulations made under the provisions of the repealed Acts shall continue to be operational till the new Statutes, Ordinances and Regulations are made as per the provisions of this Act.
		Provided that the Universities established under the provisions of the repealed Acts and now incorporated and established under this Act shall submit the Statutes for the approval of State Government not later than 01 (one) year from the date of commencement of this Act.
Transitional provisions	73	Notwithstanding anything contained in this Act and the Statutes, -
		(a) The Sponsoring Body shall appoint the First President.
		(b) The First Vice-Chancellor shall be appointed by the President in such manner and on such conditions as he may deem fit and the Vice-Chancellor shall hold office for three years.
		(c) The first Registrar and the first Finance Officer shall be appointed by the President in such manner and on such conditions as he may deem fit and said officers shall hold office for a period of three years.
		(d) the first Board of Governors shall hold office for a term not exceeding three years, and
		(e) The President shall constitute the First Board of Management, the first Finance Committee and the first Academic Council.
Minority Private Universities	74	Notwithstanding anything contained in this Act, the University established by a religious or linguistic minority of the State of Uttarakhand, shall continue to have the privileges as guaranteed by Article 30 of the Constitution of India.

Schedule 1
Existing Private Universities

S No	Name and Main Campus of the University	Name of Act	Sponsoring Body
•	Dev Sanskriti Vishwavidyalaya, Gayatrikunj- Shantikunj, Haridwar-249411	The Dev Sanskriti Vishwavidyalaya Act, 2002 (Act No. 04 of 2002.)	Shri Vedmata Gayatri Trust, Haridwar
•	UPES, P O Bithuli Via-Pran Nager, Dehradun-248007	The University of Petroleum and Energy Studies Act, 2008 (Act No. 15 of 2008.)	Hydrocarbons Education & Research Society, 2 nd floor, Okhla Industrial estate, phase III, Okhla, New Delhi 110020
•	The ICFAI University, Rajawala Road, Central Hope Town, Solapur, Dehradun - 248011	The ICFAI University Act, 2003 (Act No. 16 of 2003.)	The ICFAI society, Hyderabad, telangana
•	Mingiri Zee University, P O Sherpur, Chakrata Road, Dehradun	The Mingiri Nabh Vishwavidyalaya (University in the sky) University Act, 2003 (Act No. 17 of 2003.)	TACEIA Research Foundation, Ahmedabad, Gujarat
•	University of Patanjali, Patanjali YogPeeth, Roorkee Haridwar Road, Haridwar	The University of Patanjali Act, 2006 (Act No. 04 of 2006.)	The Patanjali YogPeeth(Trust), new delhi
•	Graphic Era Hill University Bell Road, Clement Town Dehradun	The Uttarakhand Graphic Era Hill University Act, 2011 (Act No. 12 of 2011.)	Graphic Era (Educational) Society, 166/urp road, clement town, Dehradun-248007
•	DIT University, Mussoorie, Diversion Road, Makhwala Wala, Dehradun-248009, Uttarakhand	The DIT University Act, 2012 (Act No. 10 of 2012.)	Unison education foundation, third floor, administrative block, IITs Unison University, village makhwala, uttarakhand 248009
•	IITs Unison University, Mussoorie Diversion Road, Makhwala Wala, Dehradun 248009 Uttarakhand	The IITs Unison University Act, 2012 (Act No. 13 of 2012.)	Unison education foundation, third floor, administrative block, IITs Unison University, village makhwala, uttarakhand 248009

9.	Uttarakhand University Arcadia Grant, Chandanwarl, Premnagar, Dehradun- 248007 Uttarakhand	The Uttarakhand University Act, 2012 (Act No. 11 of 2013.)	Sushila Devi Center for Professional Studies and Research society, arcadia grant, p.o chandanwarl, Premnagar, Dehradun 248007
10.	Swami Ram Himalayan University Swami Ram Nagar, Jolly Grant, Dehradun - 248148 Uttarakhand	The Himalayan University Act, 2012 (Act No. 12 of 2013.)	Himalayan Institute Hospital Trust Swami Ram Nagar Jolly Grant Dehradun 248016 Uttarakhand
11	Motherhood University Karaundi, Bhagwanpur, Roorkee (Haridwar)	The Motherhood University Act, 2014 (Act No. 05 of 2015.)	Motherhood Institute of Management Technology Society, wG-karaundi, post- bhagwanpur, roorkee 247667
12	Bhagwant Global University Uttari Jhandi Chaur, Kotdwar District Pauri - Garhwal, Uttarakhand	The Bhagwant Global University Act, 2016 (Act No. 39 of 2016.)	Bhagwant Education Foundation, New Delhi
13	Maharaja Agrasen Himalayan Garhwal University Dhaid Gaon, Block Pokhra District Pauri Garhwal- 246159, Uttarakhand	The Himalayan Garhwal University Act, 2016 (Act No. 33 of 2016.)	Jankalyan Educational Trust, 11, Naveen park, rahibabad, Ghazabad
14	Ras Bihari Bose Subharati University Katra Santour, Nanda Ki Chowki, Dehradun-248007, Uttarakhand	The Ras Bihari Bose Subharati University Act, 2016 (Act No. 35 of 2016.)	Dr Jagat Narain Subharati Charitable Trust, Dehradun
15	Shri Guru Ram Rai University, West Patel Nagar, Patel Nagar, Dehradun- 248001 Uttarakhand	The Shri Guru Ram Rai University Act, 2016 (Act No. 03 of 2017.)	Shri Guru Ram Rai Education Mission Society, Dehradun
16	Quantum University Roorkee Dehradun Highway, Mandawar, Roorkee-247162 Uttarakhand	The Quantum University Act, 2016 (Act No. 04 of 2017.)	QMD Educational & Research Foundation (Trust), 14/1, new road, Dehradun

17.	Sardar Bhagwan Singh University, Gullar Ghati Road, Balaawa, Dehradun-248161, Uttarakhand	The Sardar Bhagwan Singh University Act, 2016 (Act No. 12 of 2016.)	Gaurev. Bharti Shiksha Sansthan, Dehradun
18.	Himalayiya University, Fatehpur Tanda, Jeevanwala, Dehradun	The Himalayiya University Act, 2019 (Act No.08 of 2019.)	Himalayiya Ayurvedic Yog Evam Prakarik Chikitsa: Sansthan, Dehradun
19.	CAER University, 07 KM Roorkee Haridwar road, vardhmanpuram, roorkee district haridwar, uttarakhand	The university of Engineering and Technology Roorkee Act, 2020 (Act No.07 of 2021.)	Seth roshan Lal Jain trust, 07 km Roorkee Haridwar road, vardhmanpuram, roorkee, district haridwar
20.	Surajmal University, village dupahariya, tehsil-kichha, district udham singh nager, uttarakhand	The Surajmal university Act, 2021 (Act No.15 of 2021.)	Surajmal lakshmidewi sawartha educational trust (trust), kichha, udham singh nager, uttarakhand
21.	Dev Shooml Uttarakhand university, nagaon, manduwala, Dehradun, uttarakhand	The Dev Shooml Uttarakhand university Act, 2021 (Act No.17 of 2021.)	Uttarakhand uthan samiti, 32/4, E.C. Road, Dehradun, uttarakhand
22.	Haridwar University, 5 km, Roorkee-Haridwar Canal Road, Village Bajuhari, Roorkee, Haridwar, Uttarakhand.	The Haridwar University Act, 2022 (Act No.16 of 2023.)	The satyam education society, Roorkee college of Engineering, Roorkee to Haridwar Canal Road, Bajuhari, Roorkee, Haridwar, Uttarakhand 247667

Schedule 2

Private Universities established and incorporated under this Act

S. No.	Name and Main Campus of the University	Name of Act	Sponsoring Body
*			
*			
*			

By Order,

SHAHANSHAH MUHAMMAD DILBER DANISH,
Principal Secretary.

Statement of Objectives and reasons

Private universities have been established and incorporated by different Acts in the state. There are different provisions in the Acts of private universities and there is no uniform system for monitoring them. Therefore, it has been decided to make an umbrella act for the purpose of governing all private universities under the common law.

2- Proposed bill fulfills the above objectives.

Dr. Dhan Singh Rawat
Minister

